a Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : I introduce* the Bill.

12.58 hrs.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further consideration of the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill. I will first place the motion before the House.

Motion Moved :

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, be taken into consideration."

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : सभापति महोदय, इस विधेयक की भावना से मेरा मतभेद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की सुविधायें सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य लोगों को भी दी जानी चाहिए। इन सुविधाओं का दायरा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस दया भाव से, या जिन मजबूरियों को दृष्टि में रखते हुए, मिनिस्टरों को यह सुविधा दी जा रही है, सरकार के अधीन कार्य करने वाले अन्य वर्ग भी उसके अधिकारी हैं और उन्हें भी वैसी ही मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को भी यह सुविधा दी जाये और इसका कहीं न कहीं समावेश किया जाये। मैं समझता हूँ कि समाज में एक सुविधा-प्राप्त वर्ग, स्ट्रेटा अथवा सेक्शन का बनता जाना समाज की वर्तमान विषमता को और अधिक बढ़ाना है।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue after lunch.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[**Shri Vasudevan Nair** *in the Chair*]

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री झारखण्डे राय : मान्यवर, इस विधेयक का मंशा बहुत साफ है। देखने में यह विधेयक बहुत छोटा है। लेकिन इसके पीछे अन्तर्निहित भावनाएं ऐसी हैं जिन पर विवाद हो सकता है और होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक के पेश करने के पीछे जो भावना काम कर रही है कहीं इस भावना का विस्तार हुआ तो इसी तरह की सुविधाएं पहले सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों के लिए, फिर पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिए, और अंत में विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी हो जायं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई इस तरह की सुविधा देना भी चाहती है, विशेष रूप से किसी को आवास की सुविधा प्रदान करना भी चाहती है, तो उसकी शुरुआत नीचे से क्यों नहीं होती है? उनसे जो सबसे अकिंचन हैं, जो सब सुविधाओं से, सब चीजों से वंचित हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं है या बहुत कम है, शुरुआत वहां से क्यों नहीं होती है? इसलिए इसके पीछे अन्तर्निहित भावनाओं का समर्थन मैं नहीं कर पा रहा हूं।

मान्यवर, आज हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आवास की समस्या कितनी भयंकर है। सारे देश में लगभग 50 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सिर पर ओढ़ने के लिए केवल आसमान है और नीचे बिछाने के लिए केवल धरती है। ऐसे लोग फुटपाथों पर जीवन व्यतीत करते हैं। कलकत्ते, बम्बई, मद्रास कानपुर जैसे देश के बड़े-बड़े शहरों में ऐसे वीभत्स दृश्य

---

*Introduced with the recommendation of the President.

[श्री झारखण्डे राय]

रोज देखे जा सकते हैं । सरकारी स्थानों पर चाहे प्लेटफार्म हो, फुटपाथ हो, स्टेशन की सीढ़ियां हों या ऐसे और भी कोई अन्य स्थान हों, वहां पर सैकड़ों और हजारों आदमी ऐसे दिखाई देते हैं जिनके लिए संसार में कोई एक इंच जमीन भी नहीं है जहां वह अपना सिर छिपा सकें। तो ऐसी स्थिति में सुविधाएं यदि देनी हों, आवास की व्यवस्था यदि करनी हो तो उनके लिये पहले करना चाहिए जिनके पास नहीं है, उनके लिए नहीं जिनके पास सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं।

मैं एक बात कहना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी अब पुरानी भावनाओं से ऊपर उठें और सरकार भी उठे। ऐसी स्थिति में जब कि कांग्रेस पार्टी से सिंडीकेट-विचार के रखने वाले लोग प्रार्याप्त मात्रा में निकाल दिए गए हैं और कहा जाता है कि समाजवाद का निर्माण करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह हटा दी गई है तो अब हर चीज की कसौटी समाजवाद दृष्टिकोण से कसी जायगी ! सरकार की हर बात को, विधेयक को, कदम को समाजवाद की कसौटी पर कसा जायगा कि उस दृष्टिकोण से यह खरा उतरता है या नहीं। यह विधेयक परसों पेश हुआ और आज इस पर बहस हो रही है। इस कसौटी पर जब हम इसे कसते हैं तो देखते हैं कि उसी पुराने दृष्टिकोण से यह विधेयक बनाया गया है और यहां लाया जा रहा रहा है। अच्छा तो यह होता कि इसे वापस ले लिया जाता। पूंजीवादी विकास पद्धति और व्यवस्था का यह अन्तर्निहित अवगुण है कि जिन के पास है उनको और ज्यादा दो, जिनके पास बहुत ज्यादा है उनको इतना दो कि कोई चीज बाकी न रह जाय। यह जीवन के हर क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। शहरों में भी जो उपेक्षित स्थान हैं पानी के विषय में, बिजली के विषय में, यातायात के विषय में उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देहातों में हालत बदतर है। मुझे तो उस समय महान आश्चर्य हुआ जब कि लखनऊ में मैंने देखा, विधान सभा मार्ग पर जहां विधान सभा निर्मित है जहां अच्छे-अच्छे महल बने हुए हैं ठीक उसके पीछे के मुहल्ले में आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि केरोसीन तेल लालटेनें जलती हैं, मामूली से बिजली के बल्ब भी नहीं जलते हैं। इतनी असमानता कि जहां पर अच्छी सड़क है उसको और भी अच्छा बनाओ, उसको फर्स्ट क्लास बनाओ लेकिन जहां धूल है, मिट्टी है वहां पर कंकड़ भी न बिछाओ—यह पूंजीवादी व्यवस्था का तौर तरीका है कि जिसके पास बहुत है उसकी ओर दिये जाओ और जो गरीब जनता है उसको वैसे ही रहने दो उसकी आज कोई पूछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस दृष्टिकोण से सरकार और मन्त्री जी को अब बुनियादी परिवर्तन करना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ—इससे अनावश्यक व्यय भार बढ़ता है। जब देश इतना गरीब है, जो भी धन देश में बढ़ा उसका सही ढंग से बटवारा नहीं हुआ, तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई हैं, उसका अधिकांश हिस्सा पूंजीपतियों की थैलियों में चला गया, उसका बहुत थोड़ा भाग जनता के पास पहुंचा, ग्राम जनता के पास पहुंचा, जब यह स्थिति है तो अनावश्यक व्यय भार क्यों बढ़ाया जाय। एक-एक पैसा हमें बचाना है, एक-एक पैसे का सदुपयोग करना है। ऐसी स्थिति में इस दृष्टिकोण से भी यह विधेयक समर्थन करने योग्य नहीं है। इसकी विचारधारा चाहे अच्छी हो, लेकिन जब तक यह चीज सर्वसाधारण के लिये लागू न हो या उसके बहुत बड़े भाग के लिये लागू न कर सकें, तब तक थोड़े व्यक्तियों के लिये इस को करना या उनकी सुविधाओं को बढ़ाते जाना न्यायसंगत नहीं है।

यदि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो मन्त्रीगण कोई भिखारी नहीं होते हैं। ऐसे मन्त्री हैं जो लखपति हैं, मैं जानता हूँ, यहां नाम की जरूरत नहीं है, जिनके बाप दादाओं

से गलत सही तरीकों से बहुत कमाया है । ऐसी स्थिति में अगर वह मन्त्री नहीं रहेंगे तो क्या कठिनाई आयेगी—अगर कोई एम० पी० है तो एम० पी० फ्लैट में चला जायगा, अगर एम० एल० ए० हैं तो विधायक निवास में चला जायगा, कोई न कोई व्यवस्था तो है ही । जहाँ तक अन्तिम संस्करण की बात है, जिसकी इसमें चर्चा की गई है, वह घरों में हो सकता है एम० पी० फ्लेट में हो सकता है, विधायक निवास में हो सकता है या पैत्रिक स्थान में हो सकता है । हम सभी ऐसा करते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, जिसके कारण इस सुविधा को बढ़ाया जाय । हम मन्त्री रहे हैं । मन्त्री मण्डल छोड़ने के बाद जैसा 2 हफ्ते उसमें रहने का नियम था, उसके बाद अपने निवास स्थान में चले गये । इसलिए सुविधा को और ज्यादा बढ़ाते जाना कोई उचित दृष्टिकोण नहीं है ।

आखिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मन्त्री मण्डल से हटने के बाद जो 15 दिन की सुविधा अब तक रही है, वह पर्याप्त है, इस में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन मर्सी दया, पिटी के आधार पर, यदि कोई मर जाय तो, मरजाने की अवस्था में अवधि बढ़ा दीजिये, एक महीना कर दीजिये, लेकिन तीन महीने व ली बात अनुचित है । इसलिये इस दृष्टिकोण से भी व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से भी यह उचित विधेयक नहीं है । मैं किसी को सुविधा देने की भावना का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जहां तक इस विधेयक की व्यवहारिकता का सवाल है, इसको लागू करने का सवाल है मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूँ । पहली नवम्बर 1966 से लागू करने का सोचना भी घोर अनैतिक है । इसे नवम्बर 1969 से लागू किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि मन्त्री जी और सरकार इस पूरे विषय पर अब नये दृष्टिकोण से विचार करे, विधेयक को वापस ले और जब तक हम दूसरों को भी ये सुविधाये देने की स्थिति में नहीं जायें तब तक कुछ विशेष लोगों को ये सुविधायें बढ़ाने की चिन्ता न करें ।

MR. CHAIRMAN : Shri N. Shivappa.

AN HON. MEMBER : There is no Congress Member to speak.

MR. CHAIRMAN : There was no name from the Congress Party with me.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : I want to speak.

SHRI S. K. TAPURIAH (Palli) : Their assent can be taken for granted. They are all for privileges.

SHRI N. SHIVAPPA : I feel that there must be some limit to the seeking of certain reliefs under the ambit of law. When the Ministers are concerned with a matter which concerns their own emoluments and benefits, they have to think reasonably before putting forward certain things in black and white. But I am sorry to state that they have been careless in bringing forward this Bill, particularly the portion to which I have got my strongest and highest objection, namely :

> "It shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1969."

AN HON. MEMBER : 1966 ?

SHRI S. K. TAPURIAH : I am reading out like this portion from the Bill which has been circulated to us and which is before the House for discussion and approval by the House.

SHRI N. SHIVAPPA : They want to substitute the words 'three months' instead of 'one month' after the cessation of Ministership or on the death of the Minister. These are the two important things here. This is in order to ensure that the monetary liability may not fall on the heads of others and in order that the premises occupied by the Minister might not be vacated thereby resulting in hampering the interest of their henchmen or others. If really there is a family which is going to suffer, then I have got a soft corner for them. If there is a deserving family which is suffering, then there are, as my hon. friend has pointed

[Shri N. Shivappa]

out, people with a lot of accumulated money, which they are not prepared to part with for partaking in the government, and they can easily come to the help of such families I have no objection if such a thing is done. But so far as this particular clause is concerned, it is ridiculous on part of any same and prudent man to take this issue into consideration. I do not know the object and reason behind this particular provision. I hope that Mr. Chairman, you will be pleased to consider this aspect. In my view, this has absolutely no meaning. It is a meaningless thing. Why should it be retrospective right from November, 1966 ?

Supposing a Minister's relative or relatives has or have used the phone unauthorisedly an innumerable times for themselves or their relations and thereby they have brought the phone bill to about Rs. 6000 instead of Rs. 2000 or Rs. 1000. the point is whether it should be condoned under the guise of retrospective effect to this Bill. If the phone has been used for the sake of attending the AICC meeting which might have been convened by this gang or by that gang or by any other, with which I am not concerned, why should we give retrospective effect to this provision ?

SHRI MANOHARAN (Madras North) : They are not gangs, but groups.

SHRI N. SHIVAPPA : At least they should come out in their true colours, and admit that the premises have been utilised or that the benefits accorded under the particular legislation have been utilised in excess, by their predecessors in office, or they had misused it or they had made it a mockery and, therefore, the Government now want to bring forward this legislation ; if they do so, then certainly we would thank them. But why should there be retorspective effect to this provision ? What is the object behind this ? So, I have the highest and strongest objection to this particular provision being included in the Act. I hope that in the interests of justice, Government will not bring forward such a Bill. No sane man should bring forward such a Bill, if he wants to avoid the healthy criticism by the generous public of this country, and if he appreciates the reasonable argument advanced by my hon. friend, by me and others. I hope that this issue will be reconsidered, and other Bill will be introduced.

The second point that I am going to urge is this. This is a glaring discrimination made under this Bill. Our hon. Ministers want free houses, free allowances, or allowances, free of tax, car allpwances and so many other perquisites under the guise of this Act. Let us grant them these things ; we have no objection. Let them have these things, if they think that Ministership is a matter of some charm, it is a matter of occupying a high office, it is a matter of a superiority complex, it is a matter where the Minister has to categorise himself as different from the ordinary sections of people ; let them consider themselves to be superhuman beings or any other type of human beings. I have absolutely no objection. But my point is this that there are officials in this country who are also drawing salaries and who will also come under this particular provision of law. They have got some rules to follow, and they have to follow some Act, and like the salaried officials, the Ministers also are given some benefits and perquisities such as house rent, car allowance, travelling allowances etc. But I submit that all these perquisites should be grossed up with their income, and let them pay some tax on these things also. Why should there be any discrimination in this matter of payment of tax ? If they have evaded the tax or they want to evade the tax, and they have misused their authority, then they have brought the law into a mockery ; they have brought democracy into a mockery ; they have brought this country to a mockery, because they want to make a lot of amendments for their own benefit.

At the same time, they do not want to accord sanctity to the principle of equality of opportunity, equality of service and payment of tax to the exchequer without any discrimination, so that ultimately the people benefit. That is why they do not agree to all these emoluments and perquisites being grossed up for the purpose of payment of tax Why do they not bring forward such a law or enforce this by rules ? Why should there be this glaring and blatant discrimination and arbitrariness displayed in respect of the largest section of officials in this country ? There is a privileged

section sitting in this House which can give evasive answers to any specific question put by any party in the interest of the country. Somehow or other they want to tide over these few days; then they can go home. Many Ministers come and many go, many laws come and many laws go. These will not benefit the country and will not benefit the people.

What type of law is this? Why should they bring this kind of law? This is simply reducing law to a mockery. Why should there not be sanctity attached to law? We are responsible people discussing these things. We are processing these things. In doing so, let us not process these things as they process illicit liquor in the country in various Congress-ruled States, all the while singing slogans for prohibition. Like illicit manufacture of liquor, we are manufacturing laws in this country. Without responsibility we are bringing in laws of this type because they have got an absolute majority or can arrange a majority in connivance, conspiracy or collusion, with some Opposition groups. By such counting of heads, these laws will be passed. But whether this will be according sanctity to laws is doubtful.

I would, therefore, request the hon. Minister in charge to withdraw the enactment or at least see that this particular provision is deleted from it.

There is another matter which is deserving of our attention in connection with this matter. It has become a talk of the day that either in connection with AICC meetings during the last two decades of Congress rule or on some other pretext, the phones installed in the houses of Ministers were misused, the State cars put at their disposal for government work were misused and IAF planes have been misused. All these things have been done under the authority of law, whereas Ministers were to use these facilities put at their disposal for the specific purpose of government work only for the benefit of the people and in the service of the people. But as I said, these have been used on their own whims and fancies as if they were monarchs in this country.

Hence I suggest the appointment of a committee to go into the question of the utilisation and mis-utilisation of these facilities, utilisation for service or some other purpose, of these facilities and perquisites. In the interest of cleanliness and probity in public life, such an investigation is necessary. We have to find out whether government premises were utilised for the purpose for which they were given or for some other purpose.

While I am totally opposed to the arbitrary and discriminatory way in which the salaries and emoluments and other perquisites have been treated for income tax purposes, on the question of provision made in the Bill before us in the event of the death of a Minister, on compassionate grounds I have no objection to it.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, हाउस के सामने जो बिल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी भाई को वाजिब तौर पर एतराज हो सके। लेकिन अपोजीशन को तो हर बात पर एतराज करने की एक आदत सी बन गई है। किसी गलत बात पर एतराज करें तो सही है लेकिन जब सही बात पर भी एतराज़ करते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। डिमोक्रैसी सिर्फ कांग्रेस मैनों के लिए ही नहीं है बल्कि आपके लिए भी है। फिर कोई बड़ी भारी लग्जरीज मिनिस्टर्स के लिये मांगी जा रही हों, ऐसी बात भी नहीं है। किसी मिनिस्टर को अगर इस्तीफा देना पड़ जाये या बदकिस्मती से मौत वाके हो जाये तो उसके लिए आप से इजाजत चाहते हैं कि दो तीन महीने तक उसमें रह सकें और उसके बाद खाली कर दें। अगर मौत न भी हो, कुर्सी ही छिन जाये तो वह भी मौत के बराबर ही हादसा होता है। कुर्सी का छिनना भी बड़े से बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी हालत में मकान छोड़ने के लिये कुछ न कुछ समय तो देना ही चाहिए।...(व्यवधान)...आसमान से उतर कर कोई जमीन पर आ जाये तो उसके दिमाग के ठंडेपन के लिए थोड़ा समय चाहिए। ...(व्यवधान)... चेयरमैन साहब आप केरल के मुतािल्लक जानते हैं। अगर वजारत खिसकी तो लोगों को कंपकंपी छूट जाती है। यह बिल उन के लिए [illegible]

[श्री रणधीर सिंह]

है । केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सभी के लिए यह बिल है । ...(व्यवधान)...पालियामेंट जो बिल पास करती है वह सारे कन्ट्री पर लागू होता है । मैं चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ सेन्टर में ही नहीं बल्कि दूसरी स्टेट्स पर भी लागू होना चाहिए । अपोजीशन को चाहिए कि वे भी इसको लागू करें मैं सभी के लिए बात करता हूँ ।

चेयरमैन महोदय, अगर कोई मौत वाके हो जाती है तो 13 दिन शोक में ही गुजर जाते हैं जबकि बाहर से औरतें आती हैं और मातम करती हैं । एक महीने तक रिश्तेदार आते रहते हैं—पल्ली बिछी रहती है, वे आते हैं आकर मातमपुर्सी करते रहते हैं । उस तरफ के मेरे दोस्त चाहते हैं कि आज लाश पड़ी हुई है और अगले दिन ही मकान खाली करो । मैं समझता हूँ यह बड़ी ज्यादती की बात होगी । हर बात में दिखावा नामुमकिन बात है । आखिर जो वजीर हैं वह भी इनसान हैं । इस किस्म की अगर कोई बात हो जाती है तो उसके लिए न सिर्फ हम लोगों को रहम करना चाहिये बल्कि एखलाक और इन्सानियत की बात भी होनी चाहिए । इसमें नावाजिब तौर पर कोई बात नहीं कही गई है । जैसा शास्त्री जी के लिये कहा, इस किस्म की कोई बात नहीं है । जब ऐसा व्यू यह पार्लमेन्ट लेती है तो फिर अगर किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो फिर उस हालत में तीन महीने का अरसा कोई लम्बा नहीं है । किसी की कुर्सी छिन जाती है उसके लिये भी एक महीने का अरसा कोई ज्यादा नहीं है । ...(व्यवधान)...

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वजीर साहबान थोड़ी सी अपनी शान व शौकत कम करें । यह देश गरीबों का है । कार चलाने के लिए जो एक एक दो दो शोफर रहते हैं उनमें कमी करें । सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड ग्रेड पी एज, इनमें आस्टेरिटी करने की जरूरत है । जरूरत एक चपरासी की है लेकिन कोठी में 15 चपरासी लगे रहते हैं । उनमें आपस में जिद्द लगी रहती है कि वह नहीं करता तो मैं क्यों करूं, लिहाजा काम कोई भी नहीं करता । यह गरीबों का देश है । यह वाजिब नहीं है कि मिनिस्टर बनते ही 25 या 50 हजार का फरनीचर चाहिये पहले का अगर काफी फरनीचर पड़ा हुआ है, वह 6 महीने या साल भर पुराना भी हो गया है तो उसमें क्या बात हो गई ? फरनीचर तो दर्जनों साल चलता है । लेकिन मिनिस्टरों में कम्पटीशन होता है कि फलां वजीर की कोठी में फर्नीचर शानदार कलर का है, मेरा तो उससे भी शानदार होना चाहिए । हमें तो ज्यादा से ज्यादा किफायतशारी करनी चाहिए और यह नहीं देखना चाहिये कि इंगलैंड और अमरीका के वजीर किस तरह से रहते हैं । हमें तो ज्यादा से ज्यादा सादा रहने की कोशिश करनी चाहिए और जितना कम से कम खर्च कर सकें लग्जरीज पर वह अच्छी बात होगी । मेरे दोस्तों ने जो राई का पहाड़ बनाया है इस की कोई जरूरत नहीं थी । इस बिल को जल्दी पास करना चाहिये था. यह सब के हित की बात है । अपोजीशन वालों की भी जगह व जगह सरकारें हैं इसलिये इस में मुखालिफत की कोई गुंजायश नहीं है । कानूनी तौर पर यह बात ठीक है, अगर किसी को मकान से बेदखल करते हैं तो अदालत भी 3 या 6 महीने का मौका देती है । किसी से मकान आप अगर खरीदें तो उस को भी खाली करने के लिये कुछ मौका देते हैं । इसलिये कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इन्साफी तौर पर कौन भी तराजू पर आप यह बात तोलते हैं । हर बात की मुखालिफत करना ही अपोजीशन का काम नहीं होना चाहिए । मैं चाहूंगा कि यह बिल यूनानिमसली पास करना चाहिये । मैं पुरजोर शब्दों में इस बिल की हिमायत करता हूँ ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, मुझे आश्चर्य है कि समाजवाद का नारा लगाने वाले लोग आज इस सदन में इस बात की मांग कर रहे हैं कि मंत्रियों को और सुविधायें दी जायें। अभी मेरे मित्र, चौधरी रणधीर सिंह ने कहा कि अगर किसी मिनिस्टर को हटा दिया जाता है तो वह भी मौत के बराबर होता है। मैं इस को मानता हूं। लेकिन किसी को अगर मंत्रि पद की आशा हो और उस को मन्त्री न बनाया जाय तो उस के लिए वह भी मौत के बराबर होगा। तो यह चीज नहीं चल सकती।

एक तरफ तो यह नारा लगाया जाता है कि जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते में उन की सुविधाओं और तनख्वाहों पर सीलिंग लगायी जाय, मैं उस के पक्ष में हूं, और दूसरी तरफ मंत्रियों को और अधिक सुविधायें मिलें और ज्यादा फेसिलिटीज मिलें इस के लिए सदन में बिल लाते हैं, यह जो दो स्टैन्डर्ड हैं ये देश के सामने नहीं चल सकते। मैं बताना चाहता हूं कि मंत्रियों को आज कितनी सुविधायें हैं, एक मन्त्री के ऊपर कितना खर्च आता है ? एक सवाल के जवाब में मन्त्री जी ने कहा था कि एक कैबिनेट रैंक के मंत्री को तनख्वाह 27,000 रु० साल मिलती है, सम्पचुअरी अलाउन्स 6,000 रु०, बिल्डिंग का रेंट 7,800 रु०, बिजली के लिये 2400 रु०, फर्नीचर का रेंट 7,704 रु० और उन के सैक्रेटेरियट पर 61,800 रु० साल का खर्च आता है। मेडिकल फेसिलिटीज, ट्रेविल, स्टाफ कार आदि को सुविधायें मिला कर एक मंत्री के ऊपर 15,000 रु० महीना खर्च होता है। यह तो कानूनन जायज है। लेकिन क्या आप कह सकते है कि मंत्री अपनी ताकत का मिस यूज नहीं करते ? मंत्री की कोठी पर जितना खर्च होना चाहिये उतना ही होता है ? मेरा चार्ज है कि यह सरकार और इस के मंत्री, जितनी कानून में सुविधायें दी गयी हैं, उन से कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं और उस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं मांग करता हूं कि अगर सही माने में आप समाजवाद की बात करते हैं, नारा लगाते हैं तो खर्चे के ऊपर सीलिंग लगाइये, जो सुविधायें हैं, तनख्वाहें हैं, उन के ऊपर सीलिंग कराइये। पहले अपने आप से शुरूवात कीजिये तब लोगों के ऊपर भी उस का असर होगा। केवल नाराबाजी से लोगों की आंखों में धूल झोंकने से आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते। यह जादू थोड़े दिन का है। जब उतर जायगा तो आप के सर पर बोलेगा और आप को भारत में कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।

टेलीफोन का आप मिस यूज करते हैं। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय, यह इन दोनों गुटों का झगड़ा था, मंत्रियों और खास तौर से प्रधान मंत्री का 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का टेलीफोन का बिल अगर देखा जाय, ट्रंक और लोकल काल्स का, मैं खास तौर से ट्रंक काल्स का जिक्र करता हूं कि करस्पौंडिन्स पीरियड का पहले तीन सालों का जो ट्रन्क काल्स का इस समय का खर्चा है उस से कम से कम दस गुना अधिक खर्चा इस बार हुआ होगा और वह टेलीफोन सारे का सारा राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी पार्टी के लिये, अपनी पार्टी के एक फैक्शन के लिये इस्तेमाल किया गया।

हम ने देखा कि पार्टी फंड के लिए लाखों रु० इकट्ठे किये जाते हैं, और प्रधान मन्त्री से ले कर नीचे तक मन्त्रियों ने करोड़ों रु० पिछले ढाई साल में इकट्ठे किये हैं। एक करोड़ चार लाख रु० बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज से इकट्ठा किया गया है। सरकार बातें करती है कि हम मोनोपली खत्म करना चाहते है। क्या इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं ? हरगिज नहीं। आप बातें करते हैं कि हम कनसेन्ट्रेशन आफ वैल्थ खत्म करना चाहते हैं, बातें गरीबों की करते हैं एक मुंह से और दूसरे हाथ से गरीबों का खून चूस कर अमीरों को जेब में डालते है। जिस पार्टी के मन्त्री

[श्री कंवर लाल गुप्त]

बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज से दो, ढाई साल में एक करोड़ रु० इकट्ठा करेंगे अपने फंक्शन के लिए इकट्ठा करेंगे क्या आप ने कभी सोचा कि ये बिजनेस हाउसेज क्या यों ही पैसा दे देते हैं। अगर कोई एक लाख रु० देगा तो 50 लाख रु० का फायदा उठायेगा। माननीय रणधीर सिंह जी की शक्ल इतनी सुन्दर नहीं है कि देखते ही इतना रुपया मिल जाय। इस की जुडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिए कि ढाई साल में जो सुविधायें ऐक्ट के तहत मंत्रियों को हासिल हैं उन का कितना मिसयूज किया गया, अपनी पावर का किस तरह से गलत नाजायज फायदा उठाया गया? सरकार कहती है कि हम ने मिस यूज नहीं किया। माननीया तारकेश्वरी जी ने कहा कि एयर फोर्स के हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया गया ए० आई० सी० सी० के डेलीगेट्स को लाने के लिये। मंत्री महोदय ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। वह तो कहेंगे ही। इस की इन्डिपेंडेंट इनक्वायरी होनी चाहिए तभी सही बात का पता लगेगा। मैं चार्ज लगाता हूँ, मन्त्री महोदय इसका खंडन करें, कि ए० आई० सी० सी० के लोगों के लिये छः बंगले रिजर्व किये गये शादी के नाम से और वहां पर ए० आई० सी० सी० के डेलीगेट्स को ठहराया गया। मैं उन स्थानों के नाम भी बताता हूँ। 8, कोटला लेन का बंगला सरदार बूटा सिंह के नाम से रिजर्व किया गया, 21 विलिन्गडन क्रेसेन्ट मुर्शीद अहमद खां के नाम से, 13 अकबर रोड, कृष्णप्पा के नाम से, 3, तीन मूर्ति लेन श्री आर० पी० के नाम से, 32 औरंगजेब, शांति कोठारी के नाम से, 8, अशोक रोड, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के नाम से रिजर्व किया गया। इन्होंने शादी के लिए ये बंगले लिये जिनका रिजर्वेशन 20 तारीख से हुआ लेकिन औक्यूपेशन 16 तारीख से ही हो गया। किस की शादी हुई, मुझे नहीं मालूम। किस की शादी किस के साथ हुई मैं नहीं जानता। क्या उन के बेटों को भी शादी का निमंत्रण पत्र मिला था? क्या उन के नजदीक के माता पिता को शादी का निमन्त्रण पत्र मिला था? क्या आप ने भी किसी को निमन्त्रण पत्र भेजा। किस की शादी थी, कौन दुल्हा था और कौन दुल्हिन थी, यह कुछ नही मालूम। वहां पर ए० आई० सी० सी० के डेलीगेट्स ठहरे हुए थे। मैं चाहता हूँ कि आप इस की जांच कराइये। हम ने शादी की सेरेमनी देखी थी, लेकिन यह शादी नहीं थी। यह तो डाइवोर्स था। और मुझे ताज्जुब है कि इस डाइवोर्स की खुशियां मनायी जा रही हैं। इसी तरीके से एलेक्शन फंड्स की बात कही गई। एलेक्शन के दिनों में, मिड-टर्म पोल में...

MR. CHAIRMAN : I am afraid you are going much beyond the scope of the Bill. If you open up all kinds of subjects, I cannot prevent other members also from going into all kinds of subjects. Then, this debate cannot be controlled at all. This Bill is specifically meant for one particular purpose.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मेरी बात सुन लीजिये। मेरा कहना यह है कि जो अलाउंसेज या सेलरी हैं कानून के मुताबिक मंत्री लोग उन का मिसयूज कर रहे हैं। मैं इस का उदाहरण देना चाहता हूँ। स्वयम् प्रधान मन्त्री महोदय ने मिड-टर्म पोल में...(**व्यवधान**)... आप नये प्रिविलेज माँगने जा रहे हैं लेकिन जो एग्जिस्टिंग फेसिलिटीज हैं उन का मिसयूज हो रहा है। मिड-टर्म पोल के अन्दर एअर फोर्स के हवाई जहाजों के इस्तेमाल में लाखों रुपये खर्च किये गये और बिहार के अंदर सिक्योरिटी को छोड़ कर बाकी चीजों पर 12 लाख रुपये खर्च कि गये ...(**व्यवधान**)... और उस का एक पैसा भी काग्रेस ने पे नहीं किया। क्या यह मिसयूज नहीं है?

MR. CHAIRMAN : What is the relevance of this to the debate?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Prime Minister is entitled to have an Air Force plane for official purposes. But instead of that, she has been using it for mid-term poll...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Air Force planes are not available to the Prime Minister under the Salaries and Allowances of Minister Act. Therefore, this cannot be raised during this discussion. There are certain rules laid down for this purpose. He has a very irresponsible and false allegation. This matter has been clarified here.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप एन्क्वायरी करवा लीजिये। मन्त्री महोदय झूठ बोल रहे हैं। गलत कहते हैं। वह फेस करें एन्क्वायरी। मैं साबित करूंगा, जो मैं कह रहा हूँ।

SHRI RANDHIR SINGH : The Prime Minister herself has contradicted it.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : If charges are made with a sense of responsibility, they can be enquired into. But if they are made in this irresponsible fashion, no Government can do anything except denying it.

MR. CHAIRMAN : If the hon. member wants a debate on any subject like this, he can have it on a proper motion on some other occasion. This Bill is only concerned with amending a particular section of the Act. If you drag in all these extraneous subjects, it will be a general debate. I cannot allow it.

SHRI K. K. NAYAR (Bahraich) : It is not permissible to refer to the abuse by the ministers of the existing facilities ?

MR. CHAIRMAN : That I allowed.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am narrating instances where the Prime Minister and other ministers are misusing the facilities given to them.

MR. CHAIRMAN : You were referring to elections, etc. That is extraneous. (*Interruptions*)

SHRI RANGA (Shrikakulam) : If the Prime Minister is using Air Force Planes, does it come under "allowances" ? No, it will not come. Therefore, it is relevant to refer to such cases when the Bill is being amended to show that the Act is not implemented in a proper way, it is implemented in an extraordinary way. What is wrong with it ?

MR. CHAIRMAN : If you twist the arguments like that I do not know where it will end.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, you should do justice to me also.

MR. CHAIRMAN : He should conclude now. His time is over.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I will finish it in two minutes.

मेरा कहना यह है कि मन्त्री महोदय ने इसे डिनाई किया लेकिन बिहार, पंजाब और बंगला के मिड-टर्म पोल में प्रधान मन्त्री के ऊपर सिक्योरिटी को छोड़ कर कितना खर्च आया ? मेरा एस्टिमेट यह है कि तीनों स्टेटों में लगभग 30 लाख रुपये के खर्च किये गये और उस में से कांग्रेस ने एक पैसा भी वापस नहीं किया। वह रुपया जनता का है। उस के लिये कौन जिम्मेदार है ? वह रुपया इस देश को मिलना चाहिये। इस सरकार को चाहिये, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वह पैसा दे। यह कांग्रेस दे या वह कांग्रेस दे, मुझे इस से मतलब नहीं है, लेकिन सरकार के खजाने से जो पैसा निकला है वह गैर-काननी तरीके से निकला है और उस को वापस आना चाहिये।

एक उदाहरण दे कर मैं खत्म करूंगा। यहां जो कांग्रेस उधर की तरफ है उस के डिप्टी चीफ व्हिप को तन्ख्वाह मिलती है और डिप्टी मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है, उस को जो सुविधायें मिलती हैं वह सब उस को मिल रही हैं। क्या यह कानूनी है ? क्या यह कानून के खिलाफ नहीं है ? क्या इस पर ऐतराज नहीं उठाया गया ?

[श्री कंवर लाल गुप्त]

फिर भी सरकार उस को देती जा रही है और कानून तोड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं और मन्त्री महोदय जरा जवाब दें कि कौन कानून तोड़ रहा है? कोई कानून नहीं है कि डिप्टी चीफ व्हिप को वह 1500 रु० दिलायें चाहे एक डिप्टी चीफ व्हिप हो चाहे कई हों। अगर यहां गरीबों का सवाल है तो क्या यही सरकार का समाजवाद है। जब आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, गरीबों की बात करते हैं तो कम से कम जो मिनिमम चीजें हैं उन की गारेन्टी तो कीजिये कि तीन साल में हम इस को पूरा कर देंगे। लेकिन यह गारेन्टी देने के लिये आप तैयार नहीं हैं। हां मन्त्री लोगों के भत्ते और बढ़ने चाहिये, मंत्रियों को और सुविधायें देनी चाहिये। अगर यहां पार्लियामेंट के मेम्बरों को सुविधायें मिलेंगी तब फिर राज्य सरकारें भी वही करेंगी। क्या यही समाजवाद है और इसी समाजवाद की जड़ सरकार रखना चाहती है?

मैं कहता हूं कि सरकार इस सब चीज को नियमित करे और खर्च पर कंट्रोल करे। सुविधायें कम की जायें और एक आदर्श रक्खा जाय जिस को हम मानें। नहीं तो यह लोगों के साथ धोखा है और जो नकाब आज आप के ऊपर चढ़ी हुई है वह उठ जायेगी और आप का सही चेहरा लोगों को नजर आने लगेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Chairman, I am really sorry that Shri Gupta brought in all kinds of things on a simple amending Bill like this.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Do not over-simplify it.

SHRI R. D. BHANDARE : This Bill deals with only two contingencies. In the case of a Minister vacating office, he should be allowed to use his residence for one month and in the case of death of a Minister his family should be allowed the same facility of using the residence for three months. It is a humanitarian measure.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about the poor people in the villages ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : What has he got to do with them ?

SHRI R. D. BHANDARE : If the opposition starts bringing in irrelevant points on such a simple Bill as the present one it is failing in its duties. They must follow the rules of democracy and the role of the opposition in a democracy so that democracy can function successfully. In the present case they should adopt a humane attitude. We are dealing with a Minister who has vacated office, or the family of a Minister who has died in office. Instead of sympathising with the measure, he is talking of all sorts of things as if we can attack them in any manner we like. That is not the way of functioning under democratic rule.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I sympathise with you.

SHRI R. D. BHANDARE : You sit in the Opposition. I do not require your sympathy at all.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We will recommend your case for Deputy-Speakership.

SHRI R. D. BHANDARE : I am thankful for your sympathetic attitude but when I do not want your sympathetic attitude, why do you want to thrust it on me ? It is wonderful indeed !

When we take part in a debate on a proposition or a Bill, it should be relevant. I would also appeal to you, Mr. Chairman, to ask them to be relevant ; otherwise, we also can be irrelevant.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : (East Delhi) : On a point of order, Sir. He is speaking on the procedure of the House rather than on the Bill. He is not speaking on the Bill.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI R. D. BHANDARE ; I do not want to be irrelevant as it is their monopoly to be. I simply support the measure as it is. I am told, Government has already circulated an amendment putting "two months" instead of the words "three months". When it will be moved, I shall support it. Meanwhile I am supporting the Bill as it is without any reservation.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Mr. Chairman, we are not quite so heartless as to oppose a case when the family has to be thrown out under the existing rules and you are seeking an amendment of that. But the basic principle involved in looking after the Central ministers must be known to the world outside and the House in detail.

The present lavishness and the uncontrolled expenditure is really distressing to all of us. But we, Communists, are not really surprised at this because these 22 years of rule in Delhi and in the States where that party has ruled (*An Hon. Member* : Misruled.), they had been living a completely isolated life from the people of the country. They have no reletaion with the base, the root, the people. What is happening today is an outcome of that.

I will quote from the Government of India Gazette what a minister, on assuming his office, gets. He gets furniture worth Rs. 32,000 and electrical equipment worth Rs. 6,500.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I think, the Bill relates to what his family should get when he dies.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I will come to that. We want him to live long.

Coming back to my point, a deputy minister, for which Shri Randhir Singh is trying hard I am told, is entitled to Rs. 16,000 for furniture and Rs. 6,000 for electrical appliances, making a total of Rs. 22,000. I do not blame them.

I come to another very interesting thing. They talk about Rs. 650 as the standard rent. The cost of construction at the time of Lord Curzon, when bricks used to be sold at Rs. 10 per thousand is not the cost today. A minister living in Willingdon Crescent, Shri Fakrudin Ali Ahmed, has a total covered area of about 18,000 square feet —1,090 square metres for his own dwelling and 686 square metres for the outhouses. If you calculate it, it comes to 18,000 square feet of living space. In Calcutta, Delhi and Bombay, if yuu get something at reasonable prices, you get it at Re 1 to Rs. 1/2/-per square feet. That way, I would say, the people are paying nothing less than Rs. 25,000 per month for that man's livihg. I have quoted only one instance. There are many others. If you will kindly look at my Unstarred Question No. 2044 dated 4th August, 1969, you will get the full details.

Then, Mr. Jagjiwan Ram is occupying about 15,000 sq ft. Dr. K. L. Rao is occupying 14,000 sq. ft. Even the Deputy Minister Mr. Iqbal Singh who was in the Ministry of Works, Housing and Urban Development, let alone doing anything for Government servants, gets not less than 12,000 sq. ft. for his living. His department does not provide free bath and latrin for some of our domestic assistants.

The sum total of the perquisites that they enjoy is more than four times or even 10 times the salary they get. I would say, let the whole thing be examined by a cost accountant. You will find that a Minister at the Centre costs the people nothing less than Rs. 20,000 per month. It might even go upto Rs 30,000 per month. They are doing all this book value. It is all an eye-wash. They want to get tax-free wealth.

Then, I come to the self styled Yudhistra of the Congress Party, Shri Morarji Desai. He required Rs. 2,30,425 for maintaining a regiment of people to reply to our letters. What sort of a letter ? You write for an increment of Rs 5 for a poor Government servant. He replies in two paragraphs saying, "No, you go to hell. We will not give you that." For that, he required Rs. 2,30,425.

It is all to get tax-free benefit. Yesterday. Mrs Indira Gandhi talked a lot about money and economic matters. May I urge upon her humbly, "Doctor, treat thyself first. Prevention is better than cure. Take care of your cabinet first."

I would like to say, you amend the rules and reduce all these perquisites. You charge 6 per cent on the market value plus cost of maintenance and repairs. You do away with imported heavy cars requiring one gallon of petrol for every 10 to 12 miles.

[Shri Jyotirmoy Basu]

You ride Lagunda, Lancia, Impala and Buick. You do away with these things. It causes an irritation to the people who are starving. You go to Old Delhi and see the conditions. A man cannot get even drinking water. The people are starving.

We would like to know from the hon. Minister how much have the Ministers paid during the last three years on account of private use of cars. They are also supposed to pay to the exchequer. They are also supposed to pay for the use of extra furniture. I want to know how much money have the Ministers paid to the exchequer on these accounts.

In U.K., the *per capita* income is about 1517 dollars per annum which comes to Rs. 32 per head per day. Here, the Government says, it is one rupee and a few annas whereas we say it is only 14 paise. There, the Ministers, after deducting taxes, get much less than what in sum total these gentlemen here get when the people in our country are not getting two meals a day.

Going back to the British days, the Viceroy's Executive Councillers drew Rs. 75,000 per annum. They paid income-tax and covered other taxes also. Today, these gentlemen are getting much more than what the foreigners got ruling this country. It now seems they used to live more modestly.

Now, I would like to draw the picture of a United Front Minister in West Bengal. A Minister in West Bengal gets in all Rs. 2500 per month.

15.00 hrs.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittor) : What is the square feet area your Ministers in West Bengal occupy ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Our Ministers get Rs. 300 house rent allowance, Rs. 400 as Confidential Assistant allowance and get two PA-cum-Stenographers. They do not occupy Government quarters. One Auditor General proposed to the Government giving a lump sum amount to the Ministers for covering all the costs. I would like to know if the proposal was shelved by the Government and why they should not revert to that proposal and honour it and do all that is possible. As regards people who come here to administer the country, their living must bear a close relationship with the resources of the country and the living of the people

SHRI TENNETI VISWANATHAM : We have not heard his views on the present Bill at all.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : He has said it first.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Sir I support the Bill brought by the Government.

SHHI S. K. TAPURIAH (Pali) : Here is a meeting of the hearts.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : The Minister when he resigns, has to vacate the residence within 15 days. The Bill makes it one month. When he dies while in office, his family has been allowed by the Bill to keep the residence for two months instead of one month. It is all on humanitarian grounds. So it is a good thing. So I am supporting the Bill. When anybody dies, two months is not enough. That is my opinion. In that house the family of the deceased Minister have to perform the ceremonies according to the religious customs and so three months is necessary. I think three months must be allowed in that case. When the Minister resigns, he can be asked to vacate the residence within a month. There I have no objection. But in this case, when a Minister dies, at least three months must be allowed to enable the family to complete the ceremonies according to the Hindu custom. I am very glad that the Government has come forward with the Bill and they must implement it properly.

I would like to bring to the notice of the House one instance. When Shri Lal Bahadur Shastri died, the entire Parliament agreed that Shri Shri Shastri's family should be provided with a house and his family was provided with a residence. How respected he was and how the entire Parliament and the entire country felt it and a house was allowed. All these days there was no trouble. Now the Government has sent a bill to Shri Shastri's family—I was told and I have seen it in papers—to pay Rs. 7000 as rent for furniture. I am told that the furniture

were asked to be kept there to be moved to another house so that these things may be preserved as a museum. When the Government finds that his son is not supporting them and that he is against the Government, a bill was sent for Rs. 7000. Is it good for the Government to do that ?

The other thing is : they have sent a telephone bill to Shri Shastri's son for a period when Shri Lal Bahadur Shastri was alive. Is it good ? My only request to the Government is : is it good for them ? I only appeal to them. We have got so much respect in this country for Shri Shastri's family. Whatever be the politics, I want the Government to withdraw that demand for rent for furniture and the telephone bill.

SHRI JYOTIRMOY BASU : On a point of information, Sir. What is the date of that demand ?

MR. CHAIRMAN : Please let us not go into that. Order please.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I am not blaming anybody. But this has been done. I do not know whether the Minister knows it or whether some departmental official has done it. There is an impression among the public that this has been done wantonly. At least to clear that misunderstanding, I want the Government to see that these things are not collected from his family.

Regarding the square feet area, the Ministers are occupying, just now our friend said—he mentioned so many names—that they are occupying so many sq. ft. May I remind my hon. friend, Shri Jyotirmoy Basu, about the area he is occupying as a Member of Parliament ? when he occupies so many sq. ft. of area as a Member of Parliament, how can he complain about Ministers ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : How much ? Let my hon. friend listen to me. (*Interruption*)

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Mr. Jyotirmoy Basu. I have seen your bungalow. It is equal to the Deputy Minister's bungalow. Why do you talk like this ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Sir, it is a distortion of truth. It is a serious matter. I am entitled to have a personal explanation.

SHRI RANDHIR SINGH : Every week end he is in England He is talking about the poor.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I only said, when one criticises others, let one look back at oneself. That is the only thing that I said.

My only appeal is, let the period provided be 3 months. Let the Government say that the demand for payment of bills served on Mrs. Shastri will be withdrawn. That is all my request.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Since my name has been dragged in, I wish to say something. I have been living in a pigeon-hole.

SHRI S. KUNDU—

MR. CHAIRMAN : All Members cannot stand at the same time.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Mr. Chairman, Sir, you had been a Member of the Housing Committee. So, I would not like to carry coal to Newcastle. But I wish to dispel any worng impression in this regard and I wish to say that I had been living in two pigeon-holes in Vithalbhai Patel House. The total area would not exceed 600 sq. feet. For 2½ years I was living there. Then, after so many representations . (*Interruption*)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Sir, I don't believe that a Member is living like a pigeon.

SHRI JYOTIRMOY BASU : ...after approaching the Housing Committee, you had considered the whole thing, and you had instructed something and then I was allotted a semi-detached bungalow, one of the oldest in Delhi. It is normal accommodation given to many other M. Ps. Where is this accommodation and where is the Minister's accommodation of 20,000 sq. feet ? Sir, what he says is in bad taste and it is absolutely disgusting.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Sir, there is nothing to object to in this Bill. As my

[Shri S. Kundu]

friend said, the Bill provides certain amenities in the event of the death of a Minister. Now, the question is, the Ministers have one physical death, another is political death. In the right time they also die, as some Minister very recently died. So, the Minister can also think of providing some privileges and amenities to those Ministers who die in the right time Besides this, there is another thing. What we feel is this. The talk of socialism should stop and some sort of profession must begin. Therefore, if it is necessary that we must say something which we are talking or we must do something which we have been talking for years together it is necessary that such a thing should be practised by the Minister. I do not want to get into that dispute whether the total cost or total expenditure of a Cabinet Minister comes to 2 lakhs or 3 lakhs or 4 lakhs. The question is that the expenditure is definitely on a higher side and higher scale and that needs to be completely slashed down. Sir, there are no two opinions about that.

Those who administer the law or those who administer socialism must also live in a very humble and simple way. I would refer incidentally to Khan Abdul Ghaffar Khan who would be addressing us this evening. He has been telling us that we have forgotten Gandhiji. When Gandhiji thought of Ministers drawing a salary of Rs. 500, many people here ridiculed him and said that Gandhiji did not know that the cost of living had gone up during all this time. But it is also a fact that some Ministers are living with Rs. 500 per month today also. I do not say that they should live with just Rs. 500. But for heaven's sake, let them not say that they represent a poor country where the per capita income of 25 per cent of the people is between 23 paise and 27 paise and yet they would spend about Rs. 3 lakhs per year on themselves.

I take this opportunity to plead with the hon. Minister that he must bring forward a comprehensive Bill which will reflect a completely fresh thinking on this subject, and let us have new ideas on the salaries and allowances and other amenities for Ministers, and let us lay down some scales and let us stipulate that it should not be more than Rs. 2000 per month including all perquisites.

In the company sphere, it is said that some directors and managing directors get about Rs. 2 to 3 lakhs by way of salaries, allowance and perquisites. Some people say that it is sometimes even Rs. 5 lakhs per year. But the question is whether the Ministers should equate themselves with the company directors or managing directors. If that be so, then there is no purpose in their getting elected to the House and trying to represents the people 80 per cent to whom are poor ; if they want to live like a petty maharaja then there is no purpose in their getting elected here. If they only preach socialism but do nothing to implement it, then it is of no use. Therefore, we should bring forward legislation in such a way that people will have faith in the laws that we make. Otherwise, people will say that we are only talking wildly and doing nothing.

In 1947, when we got our Independence, the Ministers in the then Congress Government used to get a salary of Rs. 5000 ; then, it was subsequently reduced to Rs. 3000 when this Bill was brought forward in its original form. The thinking of the people who were then in Government is clearly exposed in the debates that took place here in those days. And I shall have occasion presently to quote from the debates It is something very interesting. Mr Gadgil, who was a Minister then told Sardar Patel that he could not live in such a big house, and he said 'This house haunts me ; it is a big *mahal*', and Sardar Patel told him, 'You have lived for many years in jail, but now you may stay in a *mahal*'.

While moving the parent Bill for consideration, Dr. Katju said in support of the salaries and allowances that Ministers could not live in the air ; they had to work ; they had to maintain their children, their sons and daughters had to be looked after and provided education and other things, I would submit that we have not come to make our Ministers earn some unearned income. Ministers have two kinds of income ; one is the earned income which is provided under this Act along with the perquisites, about which we have parliamentary questions here, but nobody knows any account of their unearned incomes. The whole purpose is defeated if we start living in nice luxurious flats and then we try to justify this extravagant expenditure. Therefore, I feel that we must do some fresh thinking on this matter.

I would request the hon. Minister to go into this matter in great depth and bring forward a comprehensive Bill so that we could really cut down all those amenities which are unnecessary. I think if we remove all the carpets from the MPs' flats, Ministers' flats the officers' rooms in the Central Secretariat, we shall be saving a few lakhs of rupees.

SHRI K. LAKKAPPA : Rs. 1 crore.

SHRI S. KUNDU : My hon. friend says that we shall be saving Rs. 1 crore. I may not agree with him, but definitely, we shall be saving a few lakhs of rupees ; with the aid of this amount, we could sink a tube-well in my constituency where the people who not get any drinking water now may be in a position to get drinking water. This money could be utilised for such priority items.

Times are very bitter now, and the people will not wait if people talk socialism but do not practise it. The people are now determined to throw away such people as halt and do not act. Before such a catastrophe takes place, I would warn the hon. Minister that he should bring forward a comprehensive Bill laying down a positive limit to such expenditure.

In conclusion, one more point, We say we do not have money for expenditure on the priority sectors. Let us do one thing. Let a Bill be introduced to the effect that for about 10 years no one should get salaries and allowances more then Rs. 1500 per month. Let the extra money now being given being collected into a fund. After ten years, it would be paid back to them. In the meanwhile, let this amount thus saved be used for expenditure in the priority sectors. This can be done only if Ministers also show the way and show a real will to act, not only the will to talk.

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti) : I am surprised that this Bill, innocent as it is should have taken so much time and cost the country quite a lot of money. I am sorry my young friend. Shri Jyotirmoy Basu, is not here. We had better set the example. We, MPs, have been talking about Ministers, Deputy Ministers getting this, that and the other. What do we not get ?

AN HON. MEMBER : We get nothing.

SHRI JAIPAL SINGH : I get a house. I have not measured how many square feet space it has. But that house in the private sector would cost in terms of rent about. 3,000 per month whereas I pay only Rs. 217.

Now let us be honest with ourselves. Our Ministers represent a big country. I accept the contention that they could reduce their expenditure, expenditure of putting the lights on day and night and so on. Instead of one PA, they have four, instead of one Private Secretary, they have two. All that nonsense, shoald, I think, be dispensed with. I think there is scope for economy there. There I agree with my colleagues in the Opposition. But they are very unfair to themselves when they think that Ministers can live on Rs. 500 a month.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We never suggested that.

SHRI JAIPAL SINGH : Yes, they hinted at that. Do they mean to say that when foreigners come from outside our Ministers are going to give them *dal bhath ?*

SHRI RANDHIR SINGH : *Jal pan.*

SHRI JAIPAL SINGH : Or do they think that when they go abroad, they have to live in doll houses ? What do they mean ?

The point is that there is scope for economy—there is no doubt whatsoever about it. But in my view, the Ministers are under-paid. I am very clear in my mind on that. I have been a Minister thrice—I do not know how many of my friends on the other side have been. They would be surprised if I tell them how much I pay my stenographer because I believe in paying people well. Because it will go into the Hansard, I will not mention it. But let them find out for themselves.

They talk about economy. What about MPs ? Let us set an example. Just because we are in the Opposition, let us not, therefore, run down the Ministers. There are many things MPs should not do. For instance, Ch. Randhir Singh should not shout.

SHRI RANDHIR SINGH : A very good advice. I will accept him as my *guru.*

SHRI JAIPAL SINGH : Let us be generous in our treatment of our Ministers.

[Shri Jaipal Singh]

When a Minister loses his or her job, I think he or she should be allowed to stay on for three months in the premises already alloted. We MPs are allowed one month; in case of death, two months I think I am correct. I am subject to correction. I feel it is not a question of death or losing the job. If the hon. Minister would accept my verbal amendment, he should make it three months, and three months for M.P.'s also.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): What about Government officers ?

SHRI JAIPAL SINGH: Government officers are also human beings. They are working for the country. M.P.'s are not the only people working for the country. Let us be clear about this. We thing that officers are little bearers, peons and so forth. They are men with dignity, they are serving the country, they should be given decent treatment.

I support this Bill subject to my suggestion that this one month or two months should be made three months and that he should bring another Bill to make it three months for M P's also. I tell you why. Let us see how many months Members of Parliament go on occupying or subletting their flats and bangalows after they have been defeated.

AN HON. MEMBER: Very bad.

SHRI JAIPAL SINGH: Then why don't you accept that fact ? Why are you being so self-righteous, as if only the Ministers are extravagant, officers are extravagant, and Members of Parliament are innocent.

I support this Bill subject to my amendment.

***SHRI J. H. PATEL: Mr. Chairman, Sir, I would like to make one or two suggestions on the salaries and allowances of Ministers (Amendment) Bill which is before this House. At first glance, this Bill appears to be simple and that we should give approval to it. I feel, it is quite reasonable to permit Members of his family to reside in the house on the demise of a Minister for two months as contemplated in this Bill. As regards the other provision relating to the vacation of a bunglaw on the resignation of a Minister, I oppose it because it is difficult to say how many Ministers are likely to resign from the Council of Ministers in the near future and be the beneficiaries under this provision.

Sir, I would like to refer to the economic condition of our country while discussing the provision of this Bill. What is the State of Affairs of our country ? The per capita income of our country is Rs. 462/- per annum. The average annual income of a Minister is about 75,000 rupees. In the U.S.A. the per capita income is 3,500 dollars and the annual income of a Minister there is about 35,000 dollars *i.e.*, about 2½ lakhs rupees. In Britain a Minister's income is 8,000 pounds which is fifteen times more than the per capita income. In the USA it is 15 times more and here in our country the amount received by a Minister by way of salary and allowances is 150 times higher than the per capita income. We are a debtor country and we are incapable of paying even the interest on the foreign loan that we have received. When such is the position of our country, we are spending Rs. 25,000 per day on the Prime Minister. When Dr. Lohia mentioned this in this House a few years back none believed it. In America the amount spent on the President is only 15,000 rupees per day. In Britain they are spending about 5,000 rupees per day on the Prime Minister. In our country we have passed laws for the removal of corruption. But mere enactment of laws would not solve this problem. Mere preaching to the people or to the police constable not to be corrupt would not solve the problem. Mere sermonising is not enough. We have to set a good example. Those at the top should set an example of simple living and noble action.

A few days back a Bill was brought before this House giving certain amenities and facilities to the Members of Parliament. According to that Bill we were entitled to more privileges and facilities. Because Members were given more facilities, the Minister has now come forward with this Bill giving more facilities to the Ministers. These facili-

***The original speech was delivered in Kannada.

ties would difinitely entail heavy expenditure to the exchequer. This is quite unreasonable because our country is poor and the large majority of people numbering about 29 crores are living on daily income of 30 paise only. By giving to the Members so many facilities and privileges, the Ministers and Member of Parliament are not setting a shining example and they appear to be isolating themselves from the people instead of coming closure to them. Therefore, while I would agree to the provision in the Bill relating to facilities proposed to be given to the members of his family on the demise of a Minister, I strongly oppose the provision in the Bill relating to the facilities proposed to be given to a Minister when he resigns.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister.

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon) : Could not you give me five minutes ?

MR. CHAIRMAN : I shall call you in the third reading, if you are very particular. We have taken an hour and a half while the time allotted was only one hour.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति जी, यह जो विधेयक पेश किया गया है इसके अन्तर्गत, जो इस्तीफा देते हैं ऐसे मंत्रियों के अपने निवास स्थान में रहने का समय 15 दिन से बढ़ाकर एक महीने किया जा रहा है और ऐसे मंत्रियों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है उन के परिवारों के रहने की जो अवधि है, सरकारी निवास स्थानों में, उसको एक माह से बढ़ाकर दो माह तक की अवधि की जा रही है। वैसे इस बिल में हमने तीन महीने की अवधि निश्चित की थी परन्तु सोच विचार के बाद में सरकारी संशोधन पेश कर रहा हूँ जिसमें तीन महीने के बदले दो महीने ही निश्चित कर रहे हैं।

वैसे तो इस प्रावधान के ऊपर माननीय सदस्यों में ज्यादा मतभेद नहीं है। फिर भी इस मौके का फायदा उठाकर कुछ माननीय सदस्यों ने तरह तरह की बातें कही हैं। जिन बातों का सम्बन्ध इस बिल से या इस विषय से है उनके ऊपर मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। जहाँ तक विधेयक की मूल भावना का सम्बन्ध है, उसके प्रति ज्यादा विरोध मुझे माननीय सदस्यों में दिखाई नहीं दिया। दूसरी बातों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। चौधरी रणधीर सिंह ने ठीक ही कहा है जबकि उन्होंने यह बताया कि मंत्रियों को तड़क-भड़क से बचना चाहिए। वैसे तो यह बात ठीक है कि हमारे मंत्री ज्यादा से ज्यादा तड़क-भड़क से नहीं रहते। यदि कुछ इस प्रकार के रहते हों तो वे न तो खुद अपनी सेवा करते हैं, न दल की सेवा करते हैं और न देश की ही सेवा करते हैं। तड़क-भड़क से दूर रहना बहुत जरूरी है खासकर ऐसे लोगों को जिन्हें सार्वजनिक कार्य करने पड़ते हैं। मैं एक बात विशेष रूप से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि जब भी वे मंत्रियों के खर्चे की तरफ ध्यान दें तो इस बात का खयाल रखें कि कौन सा खर्चा उनकी व्यक्तिगत हैसियत से होता है और कौन सा खर्चा उनको सरकारी हैसियत से करना पड़ता है। जहां तक निजी स्टाफ का सवाल है, यदि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पी० ए० या स्टेनोग्राफर हैं या चपरासी हैं, हो सकता है किन्हीं जगहों में वे आवश्यकता से अधिक हों पर अधिकांश जहां तक मैं समझता हूँ, वे आवश्यकता के अनुसार ही होते हैं। मंत्रियों को जहां एक ओर संसदीय, सरकारी और सार्वजनिक काम करने पड़ते हैं उसके साथ साथ कितने लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, कई जगहों में आना जाना पड़ता है, कितने लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, जिसके लिए यदि उचित ढंग से काम करना है तो उनके लिए काफी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बहुत से ऐसे खर्च जिनकी तालिका श्री कंवर लाल गुप्त ने दी, वे सरकारी कामों के ऊपर ही होते है। यदि मंत्रियों के व्यक्तिगत आंकड़ों को देखा जाये यानी जो खर्चा वे अपने पारिवारिक जीवन या स्वयं पर करते हैं वह बहुत कम होता है। आप दुनिया भर के देशों से तुलना

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

कर लीजिए—मैं कोई अमीर देशों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जो गरीब एशियाई और अफ्रीकी देश हैं, उनसे आप तुलना कीजिए तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष में मंत्रियों के ऊपर जो खर्चा होता है वह बहुत कम है। यहां पर मंत्रियों पर ज्यादा खर्चा नहीं होता है।

ऐसी बात भी नहीं है कि ऐसी मनोवृत्ति हो कि मन्त्री पद पाकर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाये, बहुत शान व शौकत और तड़क-भड़क से रहा जाये। इस संसद में आजकल जितने भी दल प्रतिनिधित्व करते हैं करीब-करीब सभी दलों के मंत्री आज हमारे देश में हैं। वे स्वयं इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह मंत्री रहते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा हिसाब लगाया जाये जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने लगाया है और हर मंत्री के सरकारी और गैर सरकारी खर्चे जोड़े जायें तो वह लम्बा चौड़ा हो सकता है। यहां पर मूल प्रश्न पर विचार करने के बदले सस्ते राजनीतिक प्रचार करने जैसी बातें कही गई, कुछ इसी प्रकार की भावना फैलाई गई और एक ठीक बहस और ठीक बातें नहीं कही गई। कंवरलाल गुप्त जी जब गरीबों की बात करते हैं तो कुछ अटपटा सा लगता है। फिर भी चूंकि गरीबों की बात की इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि मंत्रियों द्वारा जो काम किये जाते हैं वे ज्यादातर गरीबों के लिए होते हैं। स्वयं आपके मन्त्री दिल्ली में रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते है, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक उद्देश्य से ही इस पर बात करें तब तो फिर कोई रीजनेबिल बात करना मुश्किल होगा। कंवरलाल जी ने कई इधर-उधर से गलत सलत आरोप मंत्रियों पर लगाये, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता। दो एक बातें जरूर बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कि इस तरह का जो आरोप लगाया जाता है कि मन्त्री पैसा इकट्ठा करते हैं इधर उधर के कामों के लिए विशेष नियम बने हुए हैं, कोड आफ कान्डक्ट बना हुआ है। यदि उसके विरुद्ध किसी मन्त्री ने कोई कार्य किया हो तो आप वह दृष्टान्त लाइये और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : वह तो कांग्रेस प्रेसीडेन्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एकाउंट नहीं दिया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं भारतीय संसद में आश्वासन दे रहा हूं, आप उसका उपयोग कीजिए। इसके बारे में जो नियम और कोड आफ कान्डक्ट बना हुआ है उसके विपरीत किसी मिनिस्टर ने कोई आचरण किया है तो आप दृष्टान्त दीजिए। उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके पूरे तथ्य आपके सामने रख दिये जायेंगे। फिर उसके बाद ही आप कहें कि इस तरह की बात हुई है। केवल हवा में साधारण रूप से इस तरह के आरोप लगा देना, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों सरीखे व्यक्तियों के लिए कोई शोभनीय बात नहीं है।

इसके साथ साथ आपने कुछ लोगों के नाम लिए जिनके नाम से बंगले दिये गए हैं। आपने आरोप लगाया कि उसमें ए० आई० सी० सी० के मेम्बर्स ठहराये गए। मैं आपसे कहना चाहता चाहता हूं कि इसके लिए नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है। उसी के अन्तर्गत मंत्रियों अथवा पार्लियामेंट के सदस्यों को किराये पर बंगले दिये जाते हैं। यदि आपका यह आरोप हो कि हमारी पार्टी की ए० आई० सी० सी० की मीटिंग होती है उसके लिए 20 बंगले किराये पर लिए गए उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ... (**व्यवधान**)...

श्री कंवरलाल गुप्त : 20 तारीख से बंगले लिए जायें लेकिन 16 तारीख से ही ठहरा दिया जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे मेहमान आते हैं तो उनको ठहराने के लिए नियम और

कानून के अनुसार यदि हमको बंगला लेने का अधिकार हैं तो हम अवश्य उस नियम का पालन करके बंगला लेंगे और अपने मेहमानों को ठहरायेंगे और उसके साथ ही सरकारी तौर पर जो उसका किराया देना है वह देंगे। यह कोई गलत बात नहीं है। यदि इस तरह का कोई दृष्टान्त दिया जाये कि किसी मिनिस्टर या सदस्य ने किसी सरकारी निवास का दुरुपयोग किया है, पैसा नहीं दिया है, नियमों को भंग किया है तो मैं आपकी आपत्ति को समझ लूंगा कि गलत काम किया गया। लेकिन नियमों के अनुसार कोई सुविधा दी गई है उसका उपयोग किया जाता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता वे किस उद्देश्य से लिए गए--आपने स्वयं बताया कि शायद ए० आई० सी० सी० के मेम्बर्स को ठहराने के लिए लिए गए। यदि उनको ठहराने के लिए कोई लेता है तो उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

इस तरह से बहुत सी बातें कही गईं कि बहुत बड़े बंगले लिए जाते है, बंगलों का इतना क्षेत्रफल है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बंगले पुराने अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कोई नये बंगले मिनिस्टरों के लिए नहीं बनाये गए हैं। यदि आप चाहते हों कि मिनिस्टरों के लिए नये बंगले बना दिये जांय और पुराने बंगले आप लोगों को दे दिये जायें तो वैसा भी सोचा जा सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता इस तरह का खर्चा करना मुनासिब होगा। जो तीस चालिस साल पुराने बने बनाये बंगले हैं उनको सुधार करके उपयोग किया जा रहा है। यदि आप चाहते हों कि उनकी जगह पर करोड़ों रुपया खर्च करके नये बंगले बनाये जायं तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। इस बिल के द्वारा ऐसी बात नहीं की जा रही है जिससे मन्त्रियों या उनके परिवारों को कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसमें एक साधारण सी छोटी बात है। इसके सम्बन्ध में यहां पर जो बड़ी-बड़ी बातें लाई गई, मैं समझता हूँ वह उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पास कर दे।

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि वह जवाब देंगे। मैं एक ही सवाल उनसे पूछना चाहता हूं आपने कहा मैं मानता हूँ कि संसद् सदस्यों और मन्त्रियों को जो कानून में सुविधायें हैं वे लें। उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी जो बंगले लिये गये और जिस काम के लिए कह कर लिये गये उस पर मुझे एतराज है। वह यह कह कर ले सकते थे कि ए० आई० सी० सी० के लोगों के लिये चाहिये। किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन बंगले शादी के लिये गये और इस्तेमाल किये गये ए० आई० सी० सी० के डेलीगेटस को ठहराने के लिये यह एतराज की बात है।

दूसरे 20 तारीख से अलाट हुए, लेकिन उनमें से कुछ बंगले 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आक्यूपाई किये गये, यह गलत है। मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय इन बातों को मानेंगे और वह इस चीज की जांच करने के लिये तैयार हैं।

तीसरी बात यह कि मैंने यह कहा था कि प्रधान मन्त्री ने इलेक्शन फंड इकट्ठा किया, जिस को निजलिंगप्पा साहब ने भी कहा, और उसका कोई हिसाब नहीं दिया। इसका भी मन्त्री जी जवाब दें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, if you allow him a speak then you will have to give me an opportunity to reply to those points.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2—(*Amendment of section 4*)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move ;

Page 2, line 9,—

for "two months" *substitute* "one month" (3)

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I beg to move :

Page 2, line 9,—

for "two months" *substitute* "one month" (4)

Page 2, line 13,—

for "one month" *substitute* "two months" (5)

SHRI SHIV CHANDRA JHA : Sir, I have given notice of an amendment.

MR. CHAIRMAN : I am sorry, your notice was not received in time.

श्री शिव चन्द्र झा : सेकेन्ड रीडिंग से पहले अगर कोई संशोधन आ जाता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिये । इसमें क्या बात है । आप मुझे मौका दें भले ही कागज आप के हाथ में समय न न आया हो ।

MR. CHAIRMAN : It is barred because it is the same as amendment No. 3.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, though so much has been said, much of which was not relevant, some of the points have not been covered. I refer first to the ojection of my colleague, Shri Shivappa, that there is no reason why this Bill should be given retrospective effect from 1966. It implies that this is to favour some Ministers, who had overstayed their time and have not paid the rent due. In fairness to those Ministers for whom this Bill is meant. and even to all Ministers, I think the Minister in charge of the Bill should say who they are and what are the amounts proposed to be covered by giving retrospective effect.

This Bill has to be looked into in the context of the housing shortage in Delhi. If the time is extended for a Minister to stay from 15 days to one month and the family of a Minister, in the case of his death, from one month to two months without rent and one more month with rent, we have to consider the inconvenience caused to his successor. Where will he stay in the meanwhile ? If he is a Member of Parliament, he will have to be content with his humbler accommodation which is not fair to him. Also, considering the speed at which Ministers are made and unmade, by the time he becomes eligible for his accommodation after three months he may have ceased to be a Minister. It is therefore necessary that the Ministers should have their own accommodation as soon as possible after their appointment. When that is the rule in respect of Government servants I do not see any reason why the rules should be different in the case of Ministers.

Secondly, in respect of accommodation we have to remember that the number of Ministers has multiplied and even Members of Parliament are having accommodation previously reserved for officials.

If you allow this particular privilege, even after the lifetime of a Minister, the accommodation available to Government servants will be further reduced and it is not fair because Government servants are just as important to the administration as ministers.

My basic objection to these concessions is that they are invisible concessions and you cannot reckon them. Much has been said by my hon. friend, Shri Jyotirmoy Basu, about the total emoluments received by a minister in this form. He is not here but I would have liked to tell him that Svetlana had mentioned that her father, Stalin, though he received small packets of pay for himself which he did not use, was so amply provided with everything by the State that he had almost six to seven transport vehicles bringing his food every day. This kind of a thing, which is not accounted and is invisible, is not fair to the public, the taxpayer, of this country.

If the ministers want to pay themselves well and have houses, that also applies to the MP's, I am not in favour of raising the emoluments of MP's. That should be done in a proper open way. Doing it in this way also has the effect of distorting democracy. The emoluments and perquisites you are allowing to an MP may well add up to Rs. 3,000 a month That means, he is having the pay of a Secretary to Government, the highest pay in Government. Just imagine what would be the competition for this post when you have this kind of thing

paid for a minister or member who comes by election. Imagine the increased expenditure at elections. Improper expenditure will arise when this is the prize.

As far as a minister is concerned, when there is so much being given to him, what need has he for a further concession. Whatever may be the salaries and emoluments of ministers in other countries, in this country there is no need for it. If it is created, this is distorting our democracy. Neither the number of ministers nor their salaries are justified,

So, I am proposing—I cannot go very far beyond the scope of this Bill—that the time you allow for a minister's family to occupy a house without rent may be limited to one month. I heard my learned friend, Shri Randhir Singh, saying about the number of relations and the number of ceremonies which have to take place. I think we, Members of Parliament, have to set a better example to the common people of this country in curtailing these funeral ceremonies. They add to nothing. It is a form of useless social expenditure about which there should be discouragement. If you are turned out of your *biradari*, I think, it is good sometimes to be a martyr for a good cause. This kind of expenditure is not good for the country. So, I will very strongly press that the Minister accept this amendment that the period for occupation without payment of rent may be reduced to one month.

श्री प्रब्दुल गनी डार (गुडगांव) : चेयरमैन साहब जहां तक यह बिल आया है मुझे इस से पूरा इत्तफाक है । मैं समझता हूं कि इस में कोई हर्ज की बात नहीं है । लेकिन देखना यह है कि इस देश में तीन बहुत बड़े राजा कहलाये अशोक आजम, चन्द्रगुप्त और अकबर आजम—और तीनों के वक्त में यहां न सिर्फ घी और दूध की नदियां बहती थीं बल्कि केरैक्टर और विद्या की नदियां बहती थीं और दुनियां भर के विद्यार्थी तक्षशिला और नलन्दा यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे ।

मन्त्री जी ने कहा कि मिनिस्टरों को पब्लिक का काम करना पड़ता है और उन से बड़े मिलने वाले लोग आते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं आप उस पर विचार करें, क्योंकि अब इन्होंने सोशलिज्म का फैसला किया है । यूनान से जो एक तरक्की पसन्द मुल्क था, एक सफीर हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री से मिलने आया । जब वह पाटलीपुत्र पहुंचा तो उन्हों ने किसी से पूछा कि तुम्हारे प्रधान मन्त्री का महल किधर है, तो एक ने कहा कि वह सामने जो झोपड़ी है, उस में रहते हैं । वह झोंपड़ी में गया और उस वक्त प्रधान मन्त्री वहां नहीं था । इतने में एक शख्स गागर उठाये हुए कंधे पर भागा चला आ रहा था हांप रहा था, कांप रहा था । तो उस ने कहा कि मैं प्रधान मन्त्री से मिलना चाहता हूं । तो उस ने कहा कि कहिये मैं ही हूं इस देश का प्रधान मन्त्री । और वह प्रधान मन्त्री वही हैं जिन को कहते हैं चाणक्य, जिस की नीति की दुनिया में एक ही मिसाल है । उस ने कहा तुम चाणक्य हो ? चाणक्य ने कहा हां, मैं चाणक्य हूं । उस ने कहा क्या यही तुम्हारा दफ्तर या महल है ? उसने कहा हां, है । इस लिये कि अभी तक मैं सारे देशवासियों को उस तरह का महल नहीं दे सका जिस तरह का चन्द्रगुप्त का है । मैं प्रधान मन्त्री हूं और यह मेरा धर्म है कि मैं सैनिटेशन विभाग के जरिये घर घर में पानी पहुंचाया करूं । इसी लिए मैं गागर में पानी उठा रहा हूं ।

आप मानेंगे कि चाणक्य ने कोई कम काम नहीं किया । श्री शुक्ल नाराज न हों, चाणक्य ने कोई कम काम नहीं किया हालांकि वह प्रधान मन्त्री था । उस ने हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया । मुझ को इस से इत्तफाक है कि वह और जो कुछ चाहें कर लें, लेकिन इस से इत्तफाक नहीं है कि वह महल रक्खें । वह वजीर रहें, लेकिन चाणक्य की तरह । जब तक हर किसान को उसी तरह की जगह रहने के लिये न दे सकें तब तक वह भी झोपड़ी डाल कर रहें । मिनिस्टरों के लिये और मेम्बरों के लिए भी अगर झोपड़ियां डाल दी जायें तो मुझ को कोई तकलीफ नहीं होगी । मैं उस पर

[श्री अब्दुल गनी डार]

ऐतराज नहीं करूंगा। दरअसल मेरा ऐतराज यह है कि जिन की अमेनिटीज क्वीन विक्टोरिया से ज्यादा हैं, जिन की आसानियां और मौजें बड़े बड़े बादशाहों से ज्यादा हैं वह सोशलिज्म का नारा लगाते हैं। हंसी आती है कि मन्त्री महोदय श्री कंवरलाल गुप्ता पर नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अख्त्यार दिया गया है गवर्नमेंट उस का नाजायज इस्तेमाल करती है। इस पर नाराज होने की बात नही है। सच्ची बात यह है कि अगर चाणक्य गुजर कर सकते थे, अगर उस वक्त बड़े बड़े मन्त्री गुजर कर सकते थे तो आप और हम भी कर सकते हैं। मैं आप से दूर नही हूं। जब तक हम किसानों के लिए अच्छे-अच्छे मकान न बना लें, मजदूरों के लिए अच्छे मकान न बना लें तब तक हम झोपड़ी में रहने के लिये तैयार हैं और मुझे यकीन है कि जितने कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग हैं या सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं...

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : इन्होंने नार्थ ऐवेन्यू से फीरोजशाह रोड जाने की बड़ी भारी कोशिश की और सब से कहते रहे कि इस घर में मेरा गुजर नहीं होता, बंगला चाहिये। अब यहां आ कर क्यों कहते हैं इस तरह से। वह बुड्ढे हैं, और लिहाज करें, शर्म खायें....

श्री अब्दुल गनी डार : हमें कहते हैं कि शर्म आनी चाहिये। आखिर कोई हद भी होती है।

श्री मु० अ० खां : क्या यह गलत है कि आप ने कोशिश की थी ? क्या आप ने नार्थ ऐवेन्यू को छोड़ कर फीरोज शाह रोड पर बंगला नहीं लिया ?

श्री अब्दुल गनी डार : I will tell the truth.

मैं ने लिखा था कि मुझे छोटा बंगला दिया जाये लेकिन मुझे सीढ़ियों वाला बंगला न दिया जाये। यह कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं

After heart-attack, I made a request, "Please give me a small bungalow where there may be no stairs."

MR. CHAIRMAN : Please don't bring in the question of residential accommodation given to Members of Parliament. (*Interruption.*)

श्री मु० अ० खां : यह झूठ है।

SHRI ABDUL GHANI DAR : You are a liar ; you are a cent per cent liar.

श्री मु० अ० खां : यह खुद झूठे हैं। यह क्या गलत है कि अपना घर चेंज कर के बंगला लिया ? यह मोटर में चलते हैं, क्या यह गलत है ?

श्री अब्दुल गनी डार : मैं ने कहा था कि मैं हार्ट का मरीज हूं। मैं ने नीचे का एक मकान मांगा था।

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : This is very unfair. He is a heart patient ; everybody knows that. It is not proper to make an accusation like that.

شری عبدالغنی ڈار (گوڑگانوہ) چیرمین صاحب۔ جہاں تک یہ بل آیا ہے مجھے اس سے پورا اتفاق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس دیش میں تین بہت بڑے راجا کہلائے۔ اشوک اعظم، چندرگپت اور اکبر اعظم اور تینوں کے وقت میں یہاں نہ صرف گھی اور دودھ کی ندیاں بہتی تھیں بلکہ کریکٹر اور ودیا کی ندیاں بہتی تھیں اور دنیا بھر کے ودیارتھی ٹکشلا اور نالندا یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے تھے۔

منتری جی نے کہا کہ منسٹروں کو پبلک کا کام کرنا پڑتا ہے اور ان سے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ اس پر دچار کریں کیونکہ اب انھوں نے سوشلزم کا فیصلہ کیا ہے : یونان سے جو ایک ترقی پسند ملک تھا ایک سفیر ہندوستان کے پردھان منتری سے ملنے آیا۔ جب وہ پاٹلی پتر پہنچا تو انھوں نے کسی سے پوچھا کہ تمہارے پردھان منتری کا محل کدھر ہے تو ایک نے کہا کہ وہ سامنے جو جھونپڑی ہے پردھان منتری اس میں رہتے ہیں وہ جھونپڑی میں گیا اور اس وقت پردھان منتری وہاں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک شخص گاگر اٹھائے ہوئے کندھے پر لٹکا چلا آ رہا تھا اور ہانپ رہا تھا۔ کانپ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں پردھان منتری سے ملنا

چاہتا ہوں - تو اس نے کہا کہ کہتے ہیں ہی ہوں اس دیش کا پردھان منتری - اور وہ پردھان منتری وہی ہیں جن کو کہتے ہیں چانکیہ - جس کی نیتی کی ایک ہی مثال ہے - اس نے کہا - تم چانکیہ ہو - چانکیہ نے کہا - ہاں میں چانکیہ ہوں - اس نے کہا کیا کبھی تمہارا دفتر یا محل ہے - اس نے کہا ہاں ہے - اس لئے کہ ابھی تک میں سارے دیش واسیوں کو اس طرح کا محل نہیں دے سکا - جس طرح کا چندر گپت کا ہے - میں پردھان منتری ہوں اور وہ میرا دیہہ ہے کہ میں پینیشن دیہات کے ذریعہ گھر گھر پانی پہنچایا کروں - اس لئے میں گاگر میں پانی اٹھا رہا ہوں -

آپ مانیں گے کہ چانکیہ نے کوئی کم کام نہیں کیا - شری شکل ناراض نہ ہوں - چانکیہ نے کوئی کم کام نہیں کیا - حالانکہ وہ پردھان منتری تھا - اس نے ہندوستان کا نام اونچا کیا - مجھ کو اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ محل رکھیں - وہ وزیر رہیں لیکن چانکیہ کی طرح - جب تک ہر کسان کو اس طرح کی جگہ رہنے کے لئے نہ دے سکیں تب تک وہ بھی جھونپڑی ڈال کر رہیں - منتریوں کے لئے اور ممبروں کے لئے بھی اگر جھونپڑیاں ڈال دی جائیں تو مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی - میں اس پر اعتراض نہیں کروں گا - دراصل میرا اعتراض یہ ہے کہ جن کی امینیٹیز وین دکٹوریا سے زیادہ ہیں - جن کی آسانیاں اور موجیں بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ ہیں وہ سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں - ہنسی آتی ہے کہ منتری مہودے شری کنورلال گپتا پر ناراض ہوتے ہیں کیونکہ انھوں نے کہا کہ جو الاؤنس دیا گیا ہے گورنمنٹ اس کا ناجائز استعمال کرتی ہے - اس پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے - سچی بات یہ ہے کہ اگر چانکیہ ایسا کر سکتے تھے تو آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں - میں آپ سے کہتا ہوں - جب تک ہم کسانوں کے لئے اچھے مکان نہ بنائیں - مزدوروں کے لئے اچھے مکان نہ بنائیں تب تک ہم جھونپڑی میں رہنے کے لئے تیار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جتنے کمیونسٹ پارٹی کے لئے ہیں یا سوشلسٹ پارٹی کے لئے ہیں . . . .

شری م - ا - خاں (کاس گنج) انھوں نے نارتھ ایوینیو سے فیروز شاہ روڈ جانے کی بڑی بھاری کوشش کی اور سب سے کہتے رہے کہ اس گھر میں میرا گذر نہیں ہوتا - بنگلہ چاہئے - اب یہاں آ کر کہتے ہیں اس طرح سے وہ بڑھے ہیں - لحاظ کریں - شرم کھائیں - - -

شری عبدالغنی ڈار - ہمیں کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہئے - آخر کوئی حد بھی ہوتی ہے - شری م - ا - خاں - کیا یہ غلط ہے کہ آپ نے کوشش کی تھی - کیا آپ نے نارتھ ایوینیو کو چھوڑ کر فیروز شاہ روڈ بنگلہ نہیں لیا - شری عبدالغنی ڈار - آئی ول ٹیل دی ٹروتھ - میں نے لکھا تھا کہ مجھے چھوٹا بنگلہ دیا جائے - لیکن مجھے سیڑھیوں والا بنگلہ نہ دیا جائے - یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں -

After heart-attack, I made a request, "Please give me a small bungalow where there may be no stairs."

MR. CHAIRMAN : Please don't bring in the question of residential accommodation given to Members of Parliament. (*Interruption*)

شری م - ا - خاں - یہ جھوٹ ہے -

SHRI ABDUL GHANI DAR : You are a liar ; you are a cent per cent liar.

شری م - ا - خاں - یہ خود جھوٹے ہیں - یہ کیا غلط ہے کہ اپنا گھر جمع کر کے بنگلہ لیا - LIAR موٹر میں چلتے ہیں - کیا یہ غلط ہے -

شری عبدالغنی ڈار - میں نے کہا تھا کہ میں ہارٹ کا ممبر ہوں - میں نے نیچے کا مکان مانگا تھا -

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : This is very unfair. He is a heart patient ; everybody knows that. It is not proper to make an accusation like that.

श्री अब्दुल गनी डार : वह हमें गालियां दें तो भी ठीक है । लेकिन मैं तारीफ करता हूं । मैं श्री शुक्ल से एक बात कहना चाहता हूं । महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान के लिये किसी से कम काम नहीं किया । अगर वह एक छोटी सी कुटिया में बैठ कर दुनिया भर के पालिटीशियन्स से मिलते थे, दुनिया भर की पालिटिक्स पर नजर रखते थे और वहां बैठ कर उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई की रहनुमाई की तो कोई वजह नहीं कि श्री शुक्ल छोटे मकान में बैठ कर काम न कर सकें या वह इतने मसरूफ हैं कि उन को इतने बड़े महल की जरूरत है ।

इस लिये उन का जो बिल है उस को पास किया जाय लेकिन अगर सोशलिज्म को लाने के लिये जरूरत पड़े तो वह हम सब के महल और हमारे बंगले हम से छीन लें, उन को किराये पर चढ़ा दें, उन को बिजिनेस सैंटर बना दें । इस में मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा ।

[شری عبدالغنی ڈار - وہ ہمیں گالیاں دیں تو بھی ٹھیک ہے - لیکن میں تعریف کرتا ہوں - میں شری شکلا سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں - مہاتما گاندھی نے ہندوستان کے لئے کسی سے کم کام نہیں کیا - اگر وہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھ کر دنیا بھر کے پالیٹیشنس سے ملتے تھے - دنیا بھر کی پالیٹکس پر نظر رکھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر انھوں نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی رہنمائی کی تو کوئی وجہ نہیں کہ شری شکلا چھوٹے مکان میں بیٹھ کر کام نہ کر سکیں یا وہ اتنے معروف ہیں کہ ان کو اتنے بڑے محل کی ضرورت ہے -

اس لئے ان کا جو بل ہے اس کو پاس کیا جائے لیکن اگر سوشلزم
کو لانے کے لئے ضرورت پڑے تو وہ ہم سب کے محل اور ہمارے بنگلے
ہم سے چھین لیں - اُن کو کرائے پر چڑھا دیں ان کو بیزنیس سنٹر
بنا دیں - اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا -]

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : सभापति महोदय, यह एक इन्नोसेंट विधेयक है। इस में सिर्फ इतना ही है कि इस समय जो मन्त्री हट जाता है उस को पन्द्रह दिन के अन्दर मकान को खाली करना पड़ता है, इस में यह समय एक महीने के लिए किया गया है। मैं इस का विरोध नहीं करता। लेकिन साथ-साथ मैं यह बात ठीक नहीं समझता कि एक मिनिस्टर, जो डिमाक्रेसी के जरिये से पावर में आये वह इस तरह से प्रिविलेज्ड क्लास हो जाये और उस में और कामन मैन में आकाश-पाताल का अन्तर होता जाय। साथ ही साथ चाहे एम पी हों चाहे गवर्नमेंट अफसर हों, जो क्वार्टर में रहते हैं, सब के लिये एक साथ बिल लाया जाता तो अच्छा होता।

मैं चाहता हूँ कि मैं एक मिसाल दे दूं। आज चाहे मिनिस्टर हो चाहे स्टेट मिनिस्टर हो सब के पक्ष में एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है। यहां तक कि हवाई जहाज में भी चलता है। मैं एक बार हवाई जहाज से पटना से आ रहा था। मेरे साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। अब वह कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। और एक स्टेट मिनिस्टर थे। हम लोग साथ-साथ बात चीत कर रहे थे। हम लोगों ने एक साथ डिनर चाहा था। लेकिन जहां सब पैसेन्जर खाते थे वहां मिनिस्टर के खाने का इन्तजाम नहीं था। मैं बतलाऊं कि हमारे साथ कैसे फर्क किया जाता था। हवाई जहाज का स्टाफ मिनिस्टरों से कहता था कि दिस साइड और हम से कहता था कि देट साइड। इस समय जो यह डिस्क्रिमिनेशन हो गया है यह हार्ट-रेंडरिंग है। जो लोग चुनाव की बदौलत एक साथ आते हैं जब उन के साथ ऐसी बातें होती हैं खाने पर, जहां पर अलग-अलग क्लासेज नहीं हैं, इंडियन एअरलाइन्स में क्लास 1 और क्लास 2 नहीं हैं. सब एक ही फेअर दे कर चढ़ते हैं वहां पर जब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब फिर जो गरीब आदमी है, जिस की पर-कैपिटा इनकम बहुत कम है, उस को तो इन लोगों के दरवाजे पर पहुंचने का भी मौका नहीं मिलेगा।

MR. CHAIRMAN : We are now on the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill and not on Indian Airlines.

I cannot allow Members to go beyond the scope of the Bill.

SHRI B. P. MANDAL : I won't go beyond the scope. I know my limitation. Kindly be patient and hear me.

Although I support this Bill, I say that day by day there is a growing discrimination in this country between the Minister and the common man. It is not at all good. Anyway, I would request that in future whenever they bring forward any Bill, it should not be discriminatory. They talk so much about Gandhiji and they say that they are very busy and they can meet so many persons. But Gandhiji was more busy and even then he always lived in a hut whereas these peopele always want to live in palaces. Whenever they go by plane, they go at the cost of the Government and they take the security officer also with them at the cost of Government. All these things are not at all encouraging. I think the idea behind it is not very good. But, in so far as this Bill is concerned, I support it.

SHRI TENNETI VISWANATHAM *rose*—

MR. CHAIRMAN : Practically, there is nothing to discuss as far as the Bill is concerned. But when Mr Viswanatham wants to speak, naturally I cannot deny.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : I also want to speak, Sir.

16.00 hrs.

*SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Chaiman, Sir, I am

*The Original speech was delivered in Telugu.

grateful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill. It is not clear why retrospective effect is sought to be given to the provisions of the Bill. The Minister has not mentioned in his statement of Objects and Reasons anything in justification for giving a retrospective effect to the Bill We do not know its financial effect. Any legislation giving retrospective effect to any provision is not proper, especially when circumstances do not warrant such a course. Secondly, an allowance of two months for vacation of residence does not appear to be appropriate. However, we agree to this provision.

While speaking on the Bill, Shri N. P. C. Naidu mentioned that recently bills demanding furniture and telephone charges were sent to the widow of late Lal Bahadur Shastri. I thought the Minister would explain why these bills were sent at this stage. If what Shri Naidu says is correct, then the bills should be withdrawn; as, to bear it is jarring to the ear. The money involved should be very small and the Government can easily afford to waive the recovery. I support the Bill before us.

16.02 hrs

[Mr. Speaker *in the Chair*]

**SHRI E. K NAYANAR (Palghat): Mr. Speaker, sir, When we bring forward such a measure as this giving certain concessions to Ministers, we have to be very careful because are we giving the same concessions to the common people of this country? Further, these concessions are sought to be given with retrospective effect. How is it that the Ministers often become subject matter of our discussion here? Till recently, people who were Ministers are today in the opposition. Similarly, people who are today in the opposition may become Ministers tomorrow. In a way it will do us a lot of good if we have a free and frank discussion on this matter becouse in a democracy free discussion should always be encouraged.

It was mentioned here that a Minister costs about Rs. 17,000 in a month to the national exchequer. From what we have seen recently it is obvious that these people do not believe in the principle of simple living and high thinking. Our Ministers should set an example for others.

We should remember that today the earning of an average Indian is less than Re. 1/- per day whereas a Minister alone costs about Rs. 17,000/- a month. How can our common people who are poor tolerate this? It is in this context that we have to consider the Minister's salary and other governmental expenditure.

In my own state, till recently people belonging to my party namely Communist Party (Marxist) were Ministers. They had never drawn more than Rs 500/—a month. In the Karachi resolution of the Congress in 1931. Mahatma Gandhi said that the maximum salary an Indian should be paid should not be more than Rs. 500/—a month and the minimum not less than Rs. 30/—a month. Today the cost of living has gone up many times higher and today in 1969 we have officials and Ministers who are paid Rs. 3,000, Rs. 4,000 and Rs 5,000 a month. Whether it be the Minister or an official we have to understand the feelings of common people when we extend certain concessions to Ministers alone. We are supposed to be building up a socialistic society. In this context if we enact this Bill what will be the reaction of the common people in this country? Instead of facing their opposition I think it will be much better for the Government to create conditions in this country whereby people can lead a simple life. In this connection I am reminded of what was said about 200 years ago by our famous poet Kunchan Nambiar. He said;

"Rajya Karyangalil Sevikkayennoru
Vyajam Natichu Samastha Sadhukkale
Thejovadham Cheithu Vithamarji
Chukonda Jeevananthum Sukhikkunnithu Chilar."

In the name of serving the people they were infact exploited by certain princes. This was what he said about the princes who were ruling in my State in olden days. What Kunchan Nambiar said two hundred years ago are equally applicable to the conditions now prevailing in India. Our Ministers and administrators are exploiting and looting people in order to enrich themselves. Therefore, we have to be very careful when we pass such a Bill

**The original speech was delivered in Malayalam.

[Shri E. K. Nayanar]

as this. I doubt very much whether the Members who spoke in support of this measure are themselves leading a model life.

I am rather surprised that people who preach socialism and who claim to stand by the poorer sections of the society are themselves coming forward with this legislative measure giving certain concessions to Ministers alone completely ignoring the needs of the poorer sections of our society. There is, thus absolutely no justification for bringing forward this measure in the present context of things. With these words I oppose this Bill.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अगर कोई मन्त्री गुजर जाता है उसके परिवार के लिए आपने यहां इस बिल में यह रखा है कि दो महीने तक तो उसका परिवार बगैर किराये के उसमें रह सकता है और उसके अलावा एक महीने के लिए किराया दे कर रह सकता है। इस में मैं चाहता हूँ कि एक प्राविसो जोड़ दिया जाए :

'Provided the total financial assets of the deceased do not exceed Rs.5,000'.

आम तौर पर जब कोई मन्त्री हो जाता है तो उसकी आर्थिक हालत अच्छी हो जाती है। वैसे भी मंत्री की हैसियत के अलावा मोटे तौर पर शुरू से ही मन्त्री के घर की आर्थिक हालत अच्छी होती है। अगर किसी की आर्थिक हालत अच्छी हो तो क्यों उसके परिवार को मुफ्त में रहने की इजाजत दी जाए और एक महीने के लिए किराया देकर रहने की इजाजत दी जाए। यह तरीका अच्छा नहीं है। अगर किसी मन्त्री की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है उसके टोटल फाइनेंशल एसेट पांच हजार से ज्यादा के नहीं हैं, तब यह बात समझ में आ सकती है कि उस के परिवार को मुफ्त में रहने की इजाजत दी जाए दो महीने के लिए और एक महीना किराया दे कर। अगर कोई मंत्री गुजर जाता है तो दुख का वह समय होता है परिवार वालों को सामान इत्यादि समेटने में समय लगता है। मैं मानता हूँ कि हमें बेरहम नहीं होना चाहिये। वे भी इंसान हैं उसी तरह से जैसे दूसरे लोग हैं। लेकिन यदि आपको मालूम हो कि उस मंत्री का बैंक बैलेंस या उसके घर की हालत अच्छी है तब फिर क्यों आप उसके परिवार को इजाजत देते है दो महीने के लिये मुफ्त रहने की और एक महीना किराया दे कर रहने की ? कहां का इन्साफ है। हिन्दुस्तान के 75 प्रतिशत लोग तीन आने रोज पर गुजर बसर करते हैं। कोई मन्त्री चाहे कितना ही गया गुजरा न हो, उसकी हालत आम जनता से कहीं अच्छी होती है।

लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात पर हमें विशेष रूप से गौर करना चाहिये। भाववेश में हम भले ही यह कह दें कि चाणक्य पैदल चलता था, अपने कधों पर पानी लाता था और अपने कपड़े स्वयं धोता था। यह जाहिर है कि चाणक्य के युग में राजधानी एक्सप्रेस जैसी कोई ट्रेन नहीं चलती थी और न ही आज कल की अन्य सुविधायें उपलब्ध थीं। प्रश्न यह है कि इस जमाने में विज्ञान ने हमें जो सुविधायें दी हैं, क्या हम उनसे मेहरूम रहें या उनका इस्तेमाल करके अपनी एफिशेंसी बढ़ायें। मैं मानता हूँ कि जहां तक ट्रेन से सफर का संबंध है, मन्त्रियों और अन्य लोगों को फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की जरूरत नहीं है और रेलवेज में भिन्न-भिन्न क्लास डिस्टिंक्शन रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यह उचित है, क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि चूंकि चाणक्य पैदल चलता था, इसलिए हम भी बस और ट्रेन का इस्तेमाल न कर के पैदल चलें ?

सरकार को इस विषय में यह स्टडी करना चाहिए कि ऐसी कौन सी मिनिमम सुविधायें हमें चाहिए, जिनके द्वारा हम अपने काम को एफिशेंट्ली चला सकें और ऐसे कौन से काम हैं, जो फिजूलखर्ची की श्रेणी में आते हैं, जिन को नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका के अर्थ-शास्त्री, पाल बैरन, ने कहा है कि हिन्दुस्तान

में प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये का कानस्पिकुग्रस कनजम्पशन होता है, जिसमें मिनिस्टरों के टूर वगैरह शामिल है। इस खर्च पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन क्या प्रगति का यह तकाजा है कि कोई छोटा नागरिक हो या मंत्री, यह विज्ञान की मामूली सुविधाओं से महरूम रहे? हमें इस पर विचार करना है और बैलेंस निकालना है कि इतनी दूर तक हमने आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करना है और इससे आगे नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया इन बातों को दृष्टि में रखते हुए कहा करते थे कि एक्सपेंडीचर की एक सीमा निश्चित की जानी चाहिए, यदि मिनिमम 150 हो, तो मैक्सिमम 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एक्सपेंडीचर की एक सीलिंग निर्धारित कर दी जाये, तो हम विज्ञान की सुविधाओं से लाभ भी उठा सकते हैं और फिजूलखर्ची के अपराधी भी नहीं बनते हैं।

हम में से कुछ लोग भावावेश में गांधीजी की चर्चा भी करते हैं। गांधी जी भंगी की कुटिया में रहते थे, लेकिन कोई मन्त्री तो नहीं रहता है। इसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी के पास घड़ी थी और वह ट्रेन पर सफर करते थे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जो जिस मंत्री की मृत्यु हो जाती है, अगर उसके घर में रुपये, मकान या जमीन के रूप में पांच हजार रुपये से ज्यादा के एसेट्स हैं, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए और उन्हें यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इससे भावना भी पूरी हो जायेगी और फिजूलखर्ची पर भी रोक लगेगी। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस सुझाव पर गौर करें।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, इस बिल का अध्ययन करने के के बाद मेरी राय है कि हम, लोक सभा के सदस्यों, को इस बिल की आलोचना या इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक बिल पास करके अपने एलाउंसिज बढ़ाये है और कुछ अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त की है। जहां तक मैंने देखा है, इस बिल के पीछे मानवीयता की भावना है और मैं समझता हूं कि मानवीयता का भी कुछ तकाजा होता है, उसकी भी कुछ मांग होती है।

इस बिल की आलोचना केवल एक ही आधार पर की गई प्रतीत होती है कि सब मंत्री लोग मालदार होते हैं और केवल टाटा बिड़ला डालमिया के एजेंट ही मन्त्री बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक वास्तविक प्रजातन्त्रवादी देश में देहात का एक गरीब आदमी भी मिनिस्टर के पद पर बैठ सकता है और आशा है कि इस देश में भी वह दिन अवश्य आयेगा। पहले भी हमारे यहां श्री लाल बहादुर शास्त्री और किदवाई साहब जैसे आदर्श मन्त्री रहे हैं, मृत्यु के समय जिनका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था।

मैं समझता हूं कि मन्त्री पद पर बैठने का अधिकार केवल पूंजीपतियों को ही नहीं है, पैसे वालों को ही नहीं है। गरीब आदमी और अनुसूचित जातियों के लोग भी इस पद पर बैठने चाहिए और बैठेंगे। जिस आदमी के पैरों में बिवाई नहीं फटी है, वह दूसरे के पैर की पीड़ा को नहीं जान सकता है। जिसने गर्मी और सर्दी किसी छोटी झोंपड़ी में बैठ कर नहीं बिताई, जिसने नंगे बदन रह कर कष्ट सहन नहीं किया, वह समाज और जनता का भला कभी नहीं कर सकता है। हमारा देश उस दिन एक आदर्श राष्ट्र होगा, जब इस देश के गरीब आदमी अपनी योग्यता के बल पर बड़े से बड़े पदों पर सुशोभित होंगे।

अगर ऐसा कोई आदर्श मिनिस्टर मरता है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो दो महीने का प्रश्न नहीं आता है। जब तक उसके बीबी बच्चों का पुनर्वास नहीं हो जाता है, तब तक उनको उस मकान में रहने की अनुमति होनी चाहिए। अगर किसी मन्त्री की विधवा

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

और अनाथ बच्चे हैं, तो कहां फेंकेंगे उनको ? क्या अनाथालय को ? जो व्यक्ति देश के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है, उसके बच्चों को अनाथालय भेजना एक अशोभनीय बात है।

मैं यह नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की सभी बातें खराब होती हैं। इस बिल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस में और एमेंडमेंट चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा मिनिस्टर मर गया है, जो वास्तव में बहुत गरीब था, जिसकी प्रापर्टी, जमीन जायदाद नहीं है, जिसकी स्त्री और बच्चों की देख-भाल करने वाला कोई नहीं है तो गवर्नमेंट की ओर से केवल दो महीने के लिए नहीं, बल्कि स्थायी रूप से उनके रहने और शिक्षा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर देश की सेवा की है, उसके बच्चों आदि की उचित व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है।

मैं उन बरसाती पालिटीशन्ज की बात नहीं करता, जो नौकरी, मिनिस्ट्री या पावर के लिए आज एक पार्टी में होते हैं और कल दूसरी पार्टी में, जो सुबह को एक नारा लगाते है। और शाम को दूसरा नारा लगाते हैं। अपितु जो वास्तविक राजनीतिज्ञ हैं, जो जनता की सेवा करते है, वे घर फूंक तमाशा करते है। उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं और उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे त्यागी और तपस्वी व्यक्तियों को यदि कभी मिनिस्ट्री मिल गई और बाद में वे मर गये, तो उनके बच्चों को क्या बनेगा ?

मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट यह बिल लाकर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मैं इस का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : शुक्र है कि आपने अध्यक्ष का जिक्र नहीं किया। अध्यक्ष के बारे में भी सोचना पड़ेगा।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I have covered most of my points while I replied at the end of the first reading, but one or two points have been repeated and one point was left out, which Shri Tenneti Viswanatham made I do not have that information about the bills that have been sent to the family of the late Lal Bahadur Shastri, but I shall certainly find out. I have no information about it; otherwise, I would have been happy to give that information as to why this has happened or whether at all this kind of thing has been done. But I shall find out and let the hon. Member know about this matter.

I have emphasised in my earlier reply that although this matter does not concern this Bill which is before the House, the hon. Members, while they criticised the expenditure, should realise the difference between the official functioning of a Minister and his private living. If these two things were distinguished, most of the criticisms that have been made would not have came about. On personal matters, the expandi-ture of the Ministers is very, very little, and it is just equitable, compared with others of the same social status; I think it would be almost the same and nothing more. But for their official duties and discharging their official functions, sometimes they have to keep a staff, security, cars, and bungalows and many other things like that which go with the office and not with the person of a Minister. Therefore, if this matter is considered by hon. Members, these criticisms would not have been made.

I am glad, however, that most of the hon. Members who have spoken have supported the provisions that have been made in the Bill. I would again say that while we have made the provision of one month—increasing it from 15 days to one month—for a Minister who demits his office, who is asked in the meantime to make arrangements for an alternative accommodation, for a Minister who dies in office, his family has been given the option of living in the official residence free of rent for one month; if they want to continue in that same official residence, they will have to pay the rent according to the charges. In the Bill, it has been provided as two months, but I have already moved the amendment which is under consideration, reducing that

period from two months to one month for which they can stay, that is to say, out of the total of two months available to the family of the deceased Minister, one month will be with payment on the usual rent and one month without any payment. This is the limited purpose of the Bill.

Mr. Lobo Prabhu is always very diligent about his amendments, and I am always looking forward for an opportunity to accept his amendments, (*Interruption*) and I would like to accept more of his amendments, but here, his amendment does not suit the scheme of this particular enactment, and therefore, it would not be possible for me to accept his amendment.

SHRI LOBO PRABHU : From two months you have reduced it to one month as I proposed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have moved an amendment for that because your amendment does not suit the scheme of the Bill.

SHRI LOBO PRABHU : My amendment was from two to one ; yours is the same.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We have captured the spirit of your amendment. Therefore, I would request the House to accept the amendments moved by me and not accept the other amendments.

SHRI LOBO PRABHU : The point about it being given retrospective effect was raised. It is a very important point. Why are you giving retrospective effect from 1966 ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Why this is given, I will have to find out. I shall find out and lay it on the Table of the House, after I find it out.

SHRI UMANATH (Pudukkotia) : Sir, when he moves the Bill, there cannot be any question of his finding out something. He must tell us now.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I do not have the information with me at this time.

MR. SPEAKER : The question is :

Page 2, line 9, *for* "two months" *substitute* "one month" (3)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : There are two amendments. Nos 4 and 5.

Amendment No.4 is barred. I shall put Amendment No.5.

Amendment No.5 was put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 — (*Short title and Commencement*)

Amendment made :

Page 1, line 4, *for* "1967" *substitute* "1969". (2)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made :

Page 1, line 1, *for* "Eighteenth" *substitute* "Twentieth" (1)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed"

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill, as amended, be passed".

SHRI TENNETI VISWANATHAM: With regard to retrospective effect, he has not been able to tell us anything about the reason way that clause was introduced or the financial effect of it. Retrospective legislation is not good. This is a statute which will stand for all time. This retrospective effect should not be there. Even now he can move for removing that part of the Bill which gives retrospective effect to it.

SHRI RANGA (Srikakulam): Speaking for myself I would not be very much averse to the high salaries being paid to the Ministers, or some of the allowances being granted to them. Even if one or two more reasonable allowances are proposed to be given to them, I might not object. But what we object to is the immoral, illegal or extra legal manner in which the Ministers have been using their powers, privileges, position and prestige to the detriment of public interest. Recently, only a few days ago, we were told—I speak subject to correction—that the Prime Minister, the Defence Minister and some other Ministers made air-journeys to various places and sent messengers and utilized various other privileges in order to further their political purposes. Even at the time of the last mid-term elections, as the House was informed some misuse has been made of their authority and their privileges. Their prestige was never high. Unfortunately it is coming down for quite some time. We hope they would not allow it to go down further by their misdeeds.

There should be high prestige associated with ministership and that should be utilized in a very careful and wise manner. It has not been so used till now. When Pandit Nehru was the Prime Minister he imposed certain checks on Ministers, although some of his favourities did misuse their prestige. After his departure there has been deterioration in this regard. At present I am afraid, there does not seem to be any control at all over these Ministers, right down to the Deputy Ministers. I know of cases where the Defence Ministers used to go about the whole of India by special planes. Recently, some other Ministers also, the Home Minister and his encourage—how many of them and which of them is the monopoly of the Home Ministry—have also been moving on some pretext or another from one part of the country to another. They always trot out public interest.

The only test in this case can be their conscience. Unfortunately, it is coming to be blunted. I hope it would not be completely smothered. Therefore, so much depends upon the sense of character, self-respect, public interest and spirit of service to the people. Everything depends on these qualities.

Would they be kept high? If they are kept high, it would be good; the prestige of the Minister would go up, the prestige of ministership would go up and the prestige of Parliament and the country would also go up.

SHRI S. N. MISRA (Kannauj): Sir, he is making a speech and raising points which are not within the scope of the Bill during the third reading.

MR. SPEAKER: He is completely relevant to refer to them during the third reading. He is entitled to refer to them.

SHRI RANGA: Then, there has been too much of competition for ministership. It is happening at the State level and, I am afraid, this fever is going to attack the Union Cabinet also. Some steps will have to be taken to reduce this fever, to reduce this sense of competition, this terrible passion on the part of politicians and public men and parliamentarians to join this queue for ministership. One of the things that can be suggested is to institute what is known as a pension for Ministers. Such of those Ministers who continue to be Ministers with some breaks over a period of ten years, let them be given this incentive if they were to retire thereafter. Sir, you will remember that years ago one Congress President suggested it and Pandit Nehru introduced the Kamraj Plan. So, if this privilege of pension is introduced then possibly some of them may be good enough to think of retiring from Ministership and be contend with remaining along with us all, keeping company with us as mere Members, and giving the benefit of their experience to Parliament, the Ministry concerned as well as the country.

In all these directions some thought has got to be given. I am not saying these things so much as a matter of picking points

against ministers. If and when—I do not know, when—an opporunity comes for us also to be in power, it would be necessary for us to think on these lines ; otherwise, Parliament will come into contempt because ministers will bring Parliament into contempt by their own misbehaviour or by their failure to behave as well as they ought to, as people expect them to and as Parliament should expect them to. This is all I have to say.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : In the mean time, Sir, I have found out why it is necessary to give retrospective effect to this provision. Two ministers who demitted office, Sarvashri Gulzarilal Nanda and S. K. Dey, had been given to understand that they could retain their official residence after resigning office, for one month instead of 15 days and the total amount of money involved is Rs. 2,125 To cover this lapse this is being given retrospective effect.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

16.38 hrs.

WAKF (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Sir, on behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmed, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Wakf Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is a very small Amendment Bill. Firstly, it proposes to amend the definition of "net income" at it appears in the Act at present. Unfortunately, some doubts have arisen with regard to the interpretation of the term net income". Originally it was intended that the net income of a property would mean the gross income of the property after deducting the revenue cess, taxes or any other taxes which may be payable to the local authorities. But in some cases the High Courts have given a different interpretation and have tried to hold that where there is land under cultivation all expenses which have been incurred by the cultivator for cultivation operations, should also be deducted. This was not the intention of the Legislature at the time the words "net income" were used in the definition. In order to overcome this difficulty an amendment has been brought forward so as to clarify the situation and to remove the doubt which has been cast on account of the pronouncements of the High Courts.

Then, as it is a question of common knowledge, section 4 of the Act provides for the appointment of a commissioner to complete the survey of the Wakf properties situated in a particular State. Under section 5 of the Act the report of the Commissioner, after completion of the survey, is to be submitted to the State which on its part would transfer it to the Board for publication.

In several States, it would not have been possible to publish the entire list at a time and sometimes it is also physically impossible. If it is taken that the entire report would be published at a time, lot of work will suffer. Therefor, by this amendment, it is provided that, gradually, in instalments also, such reports may be published and these would be deemed to have been published as per Section 5 of the Act The question was also discussed by one of the High Courts and some doubt was expressed whether the report of the Commissioner, after completion of the survey, if published in instalments, would be a valid report under Section 5 of the Act. In order to overcome these defects this amending Bill with these two amendments has been brought forward which is a very simple Bill.

With these words I move.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Wakf Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga) : Mr. Speaker, Sir, I have no serious objection to the passage of this Bill. But I cannot countenance or approve of this piecemeal legislation amending the Wakf Act of 1954.